Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 249
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
सोमवार, 15 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 कहा- मराठा आरक्षण के जीआर से ओबीसी...

4 राष्ट्र की पहचान से विश्व की साझी भाषा तक ...

7 'सोचा जरूर पर हुआ नहीं, शुक्र है वरना ...

संक्षिप्त न्यूज

वित्त मंत्री बोलीं- शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बीमा संशोधन विधेयक

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने वाला बीमा संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीमा क्षेत्र में एफडीआई को और उदार बनाने वाला विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है? इस पर उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में, नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा के 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना, चुकता पूंजी में कमी और एक समग्र लाइसेंस का प्रावधान शामिल है। एक व्यापक विधायी प्रक्रिया के तहत, जीवन बीमा निगम अधिनियम-1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम-1999 में बीमा अधिनियम-1938 के साथ-साथ संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में, भारत में 25 जीवन बीमा कंपनियां और 34 गैर-जीवन या साधारण बीमा कंपनियां हैं, जिनमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड जैसी विशिष्ट साधारण बीमा कंपनियां शामिल हैं।

कांग्रेस ने दिया अलगाव, हम दे रहे विकास

नुमालीगढ़ में पीएम मोदी ने किया बायो-इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन

गोलाघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने नए इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे। इस उद्घाटन से पहले, पीएम मोदी ने दरांग में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।

विकसित असम, विकसित भारत

नुमालीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन 'विकसित असम, विकसित भारत' की गौरव यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि असम को आज लगभग 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिली हैं, जो राज्य के विकास को गति देंगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति 'असम'

पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने वाला राज्य है, और यहां के पेट्रोलियम उत्पाद देश के विकास में अहम भूमिका निभाते

हैं। उन्होंने बताया कि जिस नए बायो-इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, वह बांस से इथेनॉल बनाएगा, जो असम के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा, एक पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। पीएम के अनुसार, ये परियोजनाएं असम में उद्योगों को बढ़ावा देंगी, युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेंगी, और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

कांग्रेस पर सीधा हमला

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक असम और पूरे देश पर शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल में विकास की रफ्तार धीमी रही और विरासत भी संकट में रही। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने असम और नॉर्थ-ईस्ट को अलगाव, हिंसा और विवाद दिए, जबकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है।'

उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया और लाचित बोरफुकन की विरासत को सम्मान दिया। पीएम ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार असम को विकास और विरासत दोनों से समृद्ध बना रही है।

कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश

'भिखारियों के आश्रयगृह में सुनिश्चित हो गरिमापूर्ण जीवन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भिखारियों के लिए राज्य संचालित आश्रयगृह (बेगर्स होम) कोई इच्छा से दिया गया दान नहीं नहीं है, बल्कि यह एक सांविधानिक जिम्मेदारी है। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन आश्रयगृहों में गरिमापूर्ण जीवन की स्थितियां लगातार सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नियंत्रण में भिक्षावृत्ति करने वाले के लिए बने आश्रयगृहों और इसी तरह के संस्थानों में सुधारों को लागू करें, ताकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के लिए गरिमा के साथ जीवन जीने का सांविधानिक अधिकार सही मायने में सुनिश्चित हो सके।

बेंच ने कहा कि ऐसे आश्रयगृहों में मानवीय परिस्थितियां बनाए रखने में विफलता केवल प्रशासन की लापरवाही नहीं है, बल्कि यह जीवन के साथ गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि गरीब और बेसहारा लोगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी सकारात्मक होनी चाहिए। भिखारियों का आश्रयगृह राज्य संचालित एक सांविधानिक ट्रस्ट है, न कि किसी की इच्छा पर आधारित दया। इसके संचालन में सांविधानिक नैतिकता यानी स्वतंत्रता, निजता और गरिमापूर्ण जीवन की शर्तें प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भिखारियों के हर आश्रयगृह में भर्ती होने वाले व्यक्ति का चौबीस घंटे के भीतर किसी योग्य डॉक्टर से अनिवार्य रूप से मेडिकल परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी की हर महीने स्वास्थ्य जांच हो और संक्रामक व पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम, पहचान और नियंत्रण के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भिखारियों के आश्रयगृहों में स्वच्छता और साफ-सफाई के न्यूनतम मानक तय करने का निर्देश दिया। इसमें स्वच्छ पानी की उपलब्धता, शौचालय, उचित नाली व्यवस्था और कीट व मच्छर नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

शीर्ष कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया, जब दिल्ली के सीलमपुर में भिखारियों के आश्रयस्थल में पीने और भोजन बनाने के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से हैजा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रकोप फैला। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर दो साल में भिखारियों के आश्रयगृहों का स्वतंत्र और तीसरे पक्ष से निष्पक्ष ऑडिट कराना होगा।

कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ा केस लंबित, फिर भी काम जारी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जबरन आगे बढ़ा रही है, जबकि इस परियोजना की पर्यावरणीय और कानूनी मंजूरी को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक 'पर्यावरणीय आपदा' है और सरकार इसे 'बुलडोज' कर रही है। उन्होंने बताया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पेड़ों की गिनती, कटाई, लकड़ी की ढुलाई और जमीन पर मार्किंग के लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।

जयराम रमेश ने बताया कि 18 अगस्त 2022 को अंडमान और निकोबार प्रशासन ने प्रमाणित किया था कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार तय कर लिए गए हैं और जमीन हस्तांतरण की सहमति मिल चुकी है। लेकिन 18 दिसंबर 2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी मीना गुप्ता ने इस प्रमाणन को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी।

उनकी याचिका में दावा किया गया कि यह प्रमाणन वनाधिकार अधिनियम के नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

एनजीटी में भी एक केस लंबित है- जयराम रमेश

कांग्रेस नेता के अनुसार, 19 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाईकोर्ट से खुद को इस मामले में पार्टी से हटाने की अजीब मांग की। लेकिन 8 सितंबर 2025 को यही मंत्रालय स्थानीय प्रशासन से यह रिपोर्ट मांग बैठा कि जनजातीय परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर वनाधिकार अधिनियम का पालन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'इससे साफ है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का रुख साफ नहीं है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है।'

'पर्यावरणीय आपदा को जबरन लागू कर रही है सरकार'

रमेश ने कहा कि गैलेथेया बे को पहले ही 'मेजर पोर्ट' घोषित कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'वनाधिकार अधिनियम और पर्यावरणीय नियमों की खुली अनदेखी करते हुए मोदी सरकार इस पर्यावरणीय आपदा को जबरन लागू कर रही है।'

15 सीटें नहीं मिली तो अकेले 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

पटना **(एजेंसी)**। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के लिए 'करो या मरो' की स्थिति पेश करते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र गया में पत्रकारों से बात करते हुए, मांझी ने खुलासा किया कि एक दशक की स्थापना के बाद भी हम को 'मान्यता प्राप्त पार्टी' का दर्जा न मिलने से वह 'अपमानित' महसूस करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा, 'मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा पाने के लिए, मेरी पार्टी को विधानसभा में कम से कम आठ सीटें जीतनी होंगी। या, हमें कुल वोटों का छह प्रतिशत वोट मिलना चाहिए।' मांझी ने कहा, 'हम इस लक्ष्य को दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। हम एनडीए के घटक दल के रूप में कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 50 प्रतिशत से कम की स्ट्राइक रेट के साथ भी, अपेक्षित संख्या में सीटें जीत सकते

हैं। दूसरा तरीका 50-100 सीटों पर उम्मीदवार उतारना है। फिर हम इन सभी पर लगभग 10, 000 वोट हासिल कर सकते हैं और आवश्यक वोट शेयर हासिल कर सकते हैं।' उन्होने कहा कि अगर, हमें 15 से 20 सीट नहीं दी गई, तब फिर हम अकेले 50 से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, मांझी ने यह कहकर खलबली मचा दी थी कि हम 'सभी 243 सीटों' पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि, जब पत्रकारों ने उनसे अपने देश में सवाल पूछे तो उन्होंने अपनी बात से पलटते हुए स्पष्ट किया कि यह एक बयानबाजी थी जिसका सहारा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए लिया था। मांझी ने 2015 में पार्टी का गठन किया था जब उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दबाव के विरोध में जेडीयू को विभाजित कर दिया था ताकि उनकी वापसी हो सके।

'विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम', महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में बोले ओम बिरला

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि देश की महिलाएं अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से 'विकसित भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह बात संसद और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि महिलाएं आज देश के विकास में नई सोच के साथ योगदान दे रही हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर रही हैं।

ओम बिरला ने आगे संविधान निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में करीब 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने संविधान को आकार देने में अहम योगदान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के कई देशों के विपरीत, भारत ने शुरुआत से ही महिलाओं को वोट देने, समानता और न्याय का अधिकार दिया।

मोहन भागवत का दुनिया को संदेश

टकराव की जड़ श्रेष्ठता का भाव, हम सब एक हैं का मंत्र जरूरी

इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक 'परिक्रमा कृपासार' के विमोचन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की आस्था को 'प्रत्यक्ष अनुभूति' पर आधारित बताया और कहा कि यह कोई काल्पनिक आस्था नहीं, बल्कि ऐसी आस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से अनुभव कर सकता है।

भागवत ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में खुद को वैज्ञानिक कहने वाले लोगों के पास भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। इसके विपरीत, भारत की आस्था के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें प्रयास और प्रयोगों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई 'पवित्रता की चेतना और भावना' के कारण, भारत 3000 वर्षों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश था।

उन्होंने आगे कहा कि उस दौरान तकनीकी प्रगति बहुत अधिक थी, लेकिन पर्यावरण का कोई क्षरण नहीं हुआ। मानव जीवन सुखी और सुसंस्कृत था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया, लेकिन कभी किसी देश पर विजय नहीं पाई, न ही किसी के व्यापार को दबाया या किसी का धर्मांतरण किया। उन्होंने कहा, 'हम जहां भी गए, हमने सभ्यता और ज्ञान दिया, हमने शास्त्रों की शिक्षा दी और जीवन को बेहतर बनाया।'

'हम सब एक हैं' के सिद्धांत पर दिया जोर

मोहन भागवत ने विश्व में होने वाले टकरावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि लोग 'भगवान' के एक होने या अनेक होने पर बहस करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे दार्शनिकों ने हमें इस तरह के टकराव में पड़ने से रोका है और यह सिखाया है कि 'सिर्फ 'भगवान' हैं। और कोई नहीं।'

उन्होंने एकता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि दुनिया में टकराव इसलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन क्या हम सबके साथ एकता का व्यवहार करते हैं? नहीं।' उन्होंने समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग

पूरे इलाके में दहशत, मौके पर पहुंचीं 15 दमकल

अहमदाबाद **(एजेंसी)**। गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं और चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। यह घटना भरूच जिले के पानौली जीआईडीसी इलाके में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सुबह करीब 8 बजे लगी। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, यह आग किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है।

आग लगने की खबर मिलते ही, स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और तुरंत 15 से ज्यादा दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मी आग बुझाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री में मौजूद रसायनों के कारण आग पर काबू पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। आग के कारण फैल रहे जहरीले धुएं से आसपास के गांवों और औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर, प्रशासन ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है, जो इस आग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कर रही है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जा सकता है।

केरल में कांग्रेस नेता विजयन की आत्महत्या का विवाद फिर भड़का, ऑडियो लीक से नेताओं पर उठे सवाल

तिरुवनंतपुरम। केरल में कांग्रेस नेता और पूर्व जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) के कोषाध्यक्ष एन.एम. विजयन की कथित आत्महत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। विजयन और उनके बेटे जीजेश ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी बहू पद्मजा के आत्महत्या के प्रयास और एक कथित ऑडियो क्लिप लीक होने से कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार ने कहा है कि पार्टी नेताओं ने कर्ज चुकाने का वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। लीक हुई ऑडियो बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवनचूर राधाकृष्णन को यह कहते सुना गया कि पार्टी नेताओं ने विजयन परिवार से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि कलपेट्टा के विधायक टी. सिद्दीकी ने अपना वादा निभाया नहीं, जबकि मामला पहले ही सुलझाया जा सकता था। यह ऑडियो सामने आते ही कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

पद्मजा का आत्महत्या प्रयास

शनिवार को विजयन की बहू पद्मजा ने

कलाई की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। अस्पताल में भर्ती पद्मजा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने परिवार को कर्ज के बोझ से उबरने में मदद नहीं की। इससे परिवार की पीड़ा और गुस्सा और बढ़ गया है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि उन्हें ऑडियो क्लिप के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि विजयन की मौत के बाद उन्होंने एक जांच समिति बनाई थी और परिवार से बात कर रिपोर्ट केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) को सौंपी थी। लेकिन पार्टी के निर्देश पर रिपोर्ट गोपनीय रखी गई। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने किसी नेता पर आरोप नहीं लगाया है और उम्मीद जताई कि मामला सुलझ जाएगा।

विधायक टी. सिद्दीकी का पक्ष

विधायक टी. सिद्दीकी ने कहा कि परिवार के साथ एक समझौता हुआ था जिसमें तीन बिंदु तय किए गए थे। 20 लाख रुपये परिवार को तत्काल सहायता के रूप में, अस्पताल के खर्च का भुगतान और विजयन की 60 लाख रुपये की संपत्ति पर लिए गए कर्ज को पार्टी की जिम्मेदारी लेना। उन्होंने बताया कि पहले दो वादे पूरे किए जा चुके हैं और तीसरे के लिए बैंक से कर्ज घटाने की प्रक्रिया चल रही है।

जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वही मैच करा रहे

भारत-पाक मैच पर तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज

पटना **(एजेंसी)**। एशिया कप 2025 में आज होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, वही लोग इस मैच को आयोजित करा रहे हैं।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, तेजस्वी यादव ने कहा, 'प्रधानमंत्री कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, उन्हें ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी का 'साझेदार' है, क्योंकि दोनों के रिश्ते अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं।

तेजस्वी ने आगे कहा कि कभी युद्ध विराम होता है, तो कभी भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होता है, और कभी खून और पानी के रिश्ते खत्म होने की बात कही जाती है। उन्होंने इन विरोधाभासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन सब का जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए।

तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला क्रिकेट मैच है, जिसे लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ी हुई है।

भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़की शिवसेना ळँऊ का जोरदार प्रदर्शन, बीसीसीआई और आईसीसी पर भी उठाए सवाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने इसे शहीदों के अपमान से जोड़ते हुए कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू होने पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया, 26 महिलाएं विधवा हो गईं, तब क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सही है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी की पीड़ा देखकर भी हम पाकिस्तान से खेलेंगे?

सावंत ने कहा कि शिवसेना की महिला शाखा ने तय किया है कि वे अपना सिंदूर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगी, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि शहादत की आंच को अनदेखा कर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर दोस्ताना व्यवहार देश के शहीदों की शहादत के खिलाफ है।

संजय निरुपम का बयान

इसी कड़ी में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि भारत और

पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा कड़वाहट भरे रहे हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है। उसने आतंकियों को पनाह दी, उन्हें फंडिंग दी और निर्दोष भारतीयों पर हमले करवाए। निरुपम ने स्पष्ट कहा कि खेल, संस्कृति या कूटनीति किसी भी स्तर पर पाकिस्तान से संबंध नहीं होने चाहिए।

बीसीसीआई और आईसीसी पर सवाल

निरुपम ने हालांकि यह भी कहा कि बीसीसीआई और आईसीसी का तर्क है कि भारत ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय मैच रोकने का फैसला लिया है, लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में भारत का बहिष्कार टीम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद उन्होंने जोर देकर कहा कि जब बात देश की भावनाओं की आती है, तो ऐसे मैचों का विरोध करना जरूरी है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या बोले?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों ने महिलाओं के पति छीन लिए, पूरा देश उनके साथ रोया। सरकार कहती है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' जारी है, लेकिन अब वही सरकार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की बजाय दुबई में जाकर उनसे क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली में उन रेस्तरां, बार और क्लबों का बहिष्कार करेगी जो यह मैच दिखाएंगे।

सिंदूर से कैसे होगा विरोध

आप की महिला इकाई ने भी एलान किया है कि वे अपने घरों से सिंदूर लाकर पार्टी कार्यालय में जमा करेंगी और फिर इसे सरकार तक भेजेंगी। भारद्वाज ने कहा कि यह कदम सरकार को यह याद दिलाने के लिए उठाया जा रहा है कि शहादत की पीड़ा को खेल के नाम पर हल्का नहीं किया जा सकता।

टीवी सेट तोड़कर किया गया विरोध

मुंबई के कर्ले रोड और कांदिवली में कार्यकर्ताओं ने टीवी सेट तोड़े। सांसद अरविंद सावंत और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी विरोध में हिस्सा लिया। आदित्य ने कहा कि बीसीसीआई अभी भी मैच रुकवाकर यह दिखा सकता है कि वह भारत के साथ खड़ा है, लालच के साथ नहीं।

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता मिलिंद नार्वेकर ने आरोप लगाया कि यह मैच कराने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधेरे में रखकर लिया गया। वहीं पुणे में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। भारत-पाक मैच को लेकर एक ओर जहां करोड़ों दर्शक रोमांचित हैं, वहीं शहीदों के परिवारों और राजनीतिक दलों का मानना है कि यह मुकाबला देश की भावनाओं से खिलवाड़ है। सवाल यह है कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जाए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और शहादत को प्राथमिकता मिले? यही मुद्दा आज देशभर में बहस का केंद्र बना हुआ है।

महाराष्ट्र का कार्यभार संभालने ट्रेन से मुंबई पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत

मुंबई। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतरिक्त कार्यभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा गया है। रविवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार लेने मुंबई पहुंचे। सोमवार सुबह 11 बजे वह महाराष्ट्र के अतिरिक्त राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अहमदाबाद से मुंबई का सफर ट्रेन के जरिए पूरा किया। अपनी इस यात्रा का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वीडियो भी साझा किया है।

आचार्य देवव्रत अपनी पत्नी दर्शना देवी के साथ 14 सितंबर सुबह अहमदाबाद से तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए। राज्यपाल देवव्रत ने अपनी यात्रा का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व संभालने हेतु मुंबई जाने के लिए आज अहमदाबाद से मुंबई तक तेजस एक्सप्रेस से रेलयात्रा शुरु की। राजधानी मुंबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल देवव्रत का स्वागत किया।

कौन हैं आचार्य देवव्रत?

आचार्य देवव्रत एक शिक्षाविद, समाजसेवी और वैदिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है।

कैसा रहा है राजनीतिक सफर?

आचार्य देवव्रत ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत शिक्षा और समाज सेवा से की थी। 2015 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। जुलाई 2019 में वे गुजरात के राज्यपाल नियुक्त किए गए, और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में अब, 2025 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

भारत-पाक मैच पर पहलगाम पीड़ित परिवार का बयान

'ये हमारी भावनाओं से खिलवाड़,

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

दुबई में इंडिया-पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के मुकाबले के बहिष्कार की मांग की जा रही है. इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बहिष्कार का आह्वान किया है.

असावरी जगदाले ने कहा, 'मुझे लगता है कि रविवार का मैच नहीं होना चाहिए. पांच महीने पहले ही पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इतना कुछ होने के बाद भी अगर बीसीसीआई को लगता है कि उन्हें मैच कराना चाहिए तो यह गलत है।'

'मैच पीड़ितों के परिवार की भावनाओं से खिलवाड़'

असावरी उस वक्त अपने माता-पिता के साथ बैसरन घाटी में थी जब आतंकवादियों ने उसके पिता और उनके पारिवारिक मित्र कौस्तुभ गणबोटे की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि मैच की अनुमति देना पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना होगा।

'जो खेल रहे उनके लिए गहरी शर्म महसूस हो रही'

असावरी ने कहा, 'मुझे उन लोगों के लिए गहरी शर्म महसूस हो रही है जो खेलने के लिए तैयार हैं, जो खेल का आयोजन कर रहे हैं, और जो इस शाम को जयकारे लगा रहे हैं, वे पहलगाम हमले, सैनिकों के बलिदान और वर्षों से हुए ऐसे अनगिनत हमलों को भूल रहे हैं।'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मैच

बता दें, भारत और पाकिस्तान रविवार (14 सितंबर) शाम को आमने-सामने होंगे, इस साल मई में सीमा पर सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद से दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच यह पहला मैच होगा. पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।

द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंग इंडिया-पाक

सरकार की नई खेल नीति के अनुसार भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुकाबले नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप और आईसीसी प्रतियोगिताओं जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट में उनका सामना करना जारी रखेगा.

मराठा आरक्षण का विरोध तेजः

ओबीसी-बंजारा और आदिवासी संगठन ने की प्रदर्शन की तैयारी

जालना। महाराष्ट्र में अब मराठा आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। मराठों को आरक्षण देने के लिए जारी सरकारी आदेश के विरोध में जालना जिले में ओबीसी-बंजारा और आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार जब तक मराठा आरक्षण जीआर को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र और कोटा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुनबी एक कृषि प्रधान समुदाय, महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग का हिस्सा है।

बंजारा संगठन गोर सेना के अध्यक्ष संदेश चव्हाण ने कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और हैदराबाद राज्य में आरक्षण प्राप्त था। हम चाहते हैं कि हमारे समान अधिकार बहाल हों। धाराशिव निवासी 32 वर्षीय बंजारा स्नातक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। उसने अपने पीछे एसटी आरक्षण की मांग करते हुए एक नोट छोड़ा था। 11 सितंबर से बंजारा युवा जालना कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जबकि वरिष्ठ नेता हरिभाऊ राठौड़ ने 15 सितंबर को जालना और

बीड में मार्च निकालने की घोषणा की है।

आदिवासी संगठन ने बंजारा समुदाय की मांग का किया विरोध

आदिवासी संगठनों ने बंजारा समुदाय की मांग का विरोध किया है और दावा किया है कि बंजारा समुदाय को विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (वीजेएनटी) खंड के तहत पहले से ही 3 प्रतिशत कोटा का लाभ मिल रहा है। ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सतसुंग मुंधे ने चेतावनी दी कि आरक्षण बढ़ाने से ओबीसी श्रेणी में पहले से सूचीबद्ध 374 जातियों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। ओबीसी नेताओं ने 10 अक्तूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है।

वहीं मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वयक संजय लाखे पाटिल ने भी जारंगे के खिलाफ बोलते हुए दावा किया है कि उन्हें हैदराबाद राजपत्र के बारे में कोई गहन जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठों को ही लाभ मिलेगा। सरकार मराठों को धोखा दे रही है।

हैदराबाद राजपत्र क्या है?

मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के अधीन था। उनके प्रशासन ने राजपत्र में जातियों और व्यवसायों का दस्तावेजीकरण किया था। 1918 में मराठों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। जो एक ऐसी मिसाल है जिसका इस्तेमाल अब उनके ओबीसी दावे के समर्थन में किया जा रहा है।

उस समय निजाम का शासन 17 जिलों पर था, जिनमें से पांच, औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभणी और उस्मानाबाद, बाद में महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए।

मराठा आरक्षण की मांग और महाराष्ट्र में रार

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला उस समय लिया, जब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने बीते 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की थी। उनके आंदोलन के चलते दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दबाव के बीच, सरकार ने दो सितंबर को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर कहा कि जिन मराठाओं के पास पुराने दस्तावेजों में खुद को कुनबी बताया गया है, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। हालांकि, सरकार के इस कदम से ओबीसी वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके आरक्षण का हिस्सा कम हो जाएगा।

'एथेनॉल के कारण ही जिंदा है चीनी उद्योग', गडकरी बोले- इस विकल्प से गन्ना किसानों को मिलेगी राहत

मुंबई। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की चीनी उद्योग एथेनॉल की वजह से ही जिंदा बचा हुआ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एथेनॉल का विकल्प सामने नहीं आता तो गन्ना किसान और चीनी मिलें बड़ी मुश्किल में होतीं। गडकरी ने यह भी कहा कि खेती में नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है ताकि किसानों को भविष्य में पानी और लागत से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

गडकरी ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या की मुख्य वजह पानी की कमी बताई। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को पर्याप्त पानी मिलता तो उन्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। इस मौके पर गडकरी ने नाम फाउंडेशन के काम की सराहना की। यह संस्था नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे के नेतृत्व में किसानों के बच्चों और जल संरक्षण के लिए काम करती है।

खेती में तकनीक की जरूरत

भाजपा नेता गडकरी ने जोर देकर कहा कि खेती में तकनीक को लाना अब अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कई प्रयोग पहले से ही शुरू हो चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीकें ही किसानों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ा सकती हैं।

एथेनॉल से मिला सहारा

गडकरी ने कहा कि भारत हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात करता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से इस बोझ को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गन्ने की पैदावार और चीनी उत्पादन अधिक होने की वजह से चीनी उद्योग संकट में था, लेकिन एथेनॉल ने इसे संभाल लिया।

कांग्रेस का हमला और भाजपा का जवाब

हाल ही में कांग्रेस ने गडकरी पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने दावा किया कि गडकरी एथेनॉल उत्पादन को लेकर आक्रामक लॉबिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीति से इन कंपनियों को फायदा हुआ। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह सिर्फ झूठे दावे करती है, जिनके पास कोई सबूत नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट और ई20 पर विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका खारिज की थी, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई20) को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि करोड़ों वाहन मालिकों को ऐसी ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी रही, जहां कई लोगों ने माइलेज 20 प्रतिशत तक घटने का दावा किया।

सोशल मीडिया विवाद पर गडकरी का बयान

गडकरी ने सोशल मीडिया पर चल रही बहस को पेड कैंपेन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक रूप से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि ई20 को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अन्य हितधारकों के बीच साफ-सुथरी सहमति है। उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि किसानों और उद्योग दोनों को नया सहारा देता है।

फर्जी डिलीवरी बॉक्स देकर बदमाश ने दिया झांसा, महिला की चेन लूटकर फरार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नागपुर।महाराष्ट्रके नागपुर शहर के चिंतामण नगर इलाके से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बदमाश ने बड़ी चालाकी से डिलीवरी ब्वॉय का भेष बनाकर एक महिला को निशाना बनाया. मामला तब सामने आया जब पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

युवक ने डिलीवरी ब्वॉय की तरह पहन रखे थे कपड़े

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक डिलीवरी ब्वॉय की तरह कपड़े पहनकर महिला के घर पहुंचा. उसके हाथ में एक डिब्बा था जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऑनलाइन कंपनी का पार्सल देने आया हो. आरोपी ने दरवाजे पर खड़े होकर महिला को झांसा दिया और कहा कि आपके लिए डिलीवरी आई है. महिला बिना शक किए गेट तक पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बदमाश ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी ने फर्जी डिलीवरी बॉक्स देने का नाटक करते हुए अचानक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और तेजी से भाग खड़ा हुआ. यह सब कुछ चंद सेकंडों में हो गया. महिला कुछ समझ पाती, तब तक आरोपी वहां से काफी दूर निकल चुका था।

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की

वारदात की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में आरोपी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान में मदद मिलेगी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी छानबीन शुरू कर दी है।

यह घटना इलाके के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है. लोगों का कहना है कि अब अपराधी नए-नए तरीके अपनाकर वारदात कर रहे हैं. इससे आम नागरिकों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. पुलिस ने अपील की है कि लोग किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा न करें और बिना पुष्टि के गेट खोलने से बचें।

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI का बड़ा एक्शन, बैंकॉक से आए नशे के 3 सौदागरों को धर दबोचा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की राजस्व खुफिया निदेशालय की मुंबई जोनल यूनिट ने एक सूचना के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। DRI की टीम ने एयरपोर्ट से नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है. टीम का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक, DRI की मुंबई जोनल यूनिट ने एक सूचना के आधार पर बैंकॉक से आए दो भारतीय यात्रियों को रोका और उनकी चेक-इन बैग की तलाशी ली। जांच के दौरान बैग से 39 पैकेट बरामद हुए, जिनमें हरे रंग का गांठदार, तीव्र गंध वाला पदार्थ पाया गया। रासायनिक जांच में यह पदार्थ कैनबिस/हाइड्रोपोनिक वीड निकला।

टीम ने रिसीवर को भी पकड़ा

DRI के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कुल 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया, जिसमें से 19.6 किलो प्रत्येक यात्री के बैग से मिला। बाद की कार्रवाई में एक और व्यक्ति को, जो इस खेप का रिसीवर था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है.

DRI नेटवर्क को खंगालने में जुटी

अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम, 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है. पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी पिछले काफी समय से गांजा तस्करी का काम कर रहे थे. आरोपी विदेश से लाए इस गांजे को ज्यादा रेटों में यहां अवैध रूप से बेचते थे. आरोपियों के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

कोर्न फलेक्स के डिब्बे में लाए थे गांजा

पकड़े गए आरोपियों ने एयरपोर्ट पर चेकिंग से बचने के लिए गांजे को कोर्न फलेक्स के डिब्बे में डाला हुआ था. सूत्रों से पता चला है कि जब ऐंटी टीम ने आरोपियों को हिरासत में लिया तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोर्न फलेक्स है. जब टीम ने डिब्बों की जांच की तो उनमें गांजा निकला. इसके बाद आरोपियों को पकड़कर उनके जरिए ही रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

250 करोड़ का फ्लाईओवर, 2 महीने में बर्बाद! डोंबिवली पालावा फ्लाईओवर ने खोली भ्रष्टाचार की पोल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के डोंबिवली पालावा फ्लाईओवर को लेकर इस समय लोगों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही है. यह फ्लाईओवर बनाने में पूरे 6 साल लगे और करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इतने लंबे इंतजार और भारी-भरकम खर्च के बाद जब फ्लाईओवर तैयार हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि अब ट्रैफिक की परेशानी कुछ हद तक कम होगी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्घाटन के सिर्फ दो महीने बाद ही इसकी हालत खस्ता हो गई है.

फ्लाईओवर देख लोगों ने उठाए सवाल

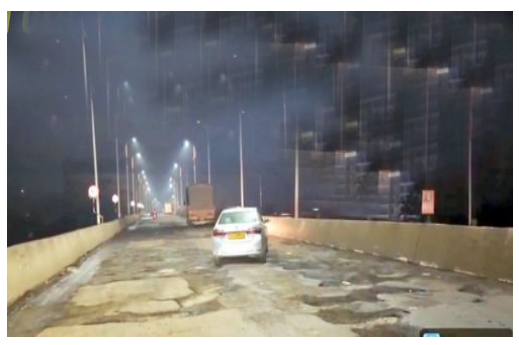

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर दरारें, गड्ढे और निर्माण कार्य की खराब क्वालिटी साफ दिख रही है. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सड़क इतनी जल्दी क्यों टूटने लगी?

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फ्लाईओवर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है. 250 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद यदि ढांचा दो महीने भी ठीक से नहीं टिक पाया तो यह साफ बताता है कि काम में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई होगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह केवल पैसों की लूट है और इसमें शामिल अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर मामलों की तरह यहां भी शायद कोई जिम्मेदार सजा नहीं पाएगा.

यह स्थिति न सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी है बल्कि आने वाले समय में लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है. फ्लाईओवर पर बढ़ते गड्ढे कभी भी बड़ा हादसा करा सकते हैं।

सीएम फडणवीस का विपक्ष को जवाब

कहा- मराठा आरक्षण के जीआर से ओबीसी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ी रार के बीच विपक्ष के आरोपों का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठा कोटा जीआर से ओबीसी वर्ग के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। ओबीसी के लिए तय लाभ फर्जी लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी और मराठों सहित सभी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर अतिवादी राजनीति करने और भय पैदा करने का आरोप लगाया।

पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा कोटा के संबंध में जारी सरकारी आदेश (जीआर) ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करने वाला है। एक भी फर्जी व्यक्ति को ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। फर्जी का मतलब है जो ओबीसी नहीं हैं। जीआर में ऐसी सावधानी बरती गई है। 2014 से ओबीसी कल्याण से संबंधित सभी निर्णय उनकी सरकार द्वारा लिए गए हैं।

सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। हम ओबीसी के लिए विभिन्न

योजनाएं लेकर आए। ओबीसी के लिए महा ज्योति स्थापित की और पिछली सरकार के कार्यकाल में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा बहाल किया। इसलिए ओबीसी जानते हैं कि उनके कल्याण की चिंता किसे है?

सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार और पिछली सरकारों के तहत ओबीसी के लिए किए गए कार्यों पर बहस होनी चाहिए। विपक्ष केवल राजनीति का सहारा लेता है, लेकिन हम ओबीसी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, हम मराठा समुदाय और अन्य सभी समुदायों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठों और ओबीसी के बीच बढ़ती दरार तब तक कम नहीं होगी जब तक दोनों समुदायों के नेता लोगों को इस मुद्दे के बारे में सही तथ्य नहीं बताएंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिनके पास कुनबी होने का रिकॉर्ड होगा। ऐसे रिकॉर्ड के बिना किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसलिए ओबीसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

सीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर अतिवादी राजनीति हो रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया है। इससे ओबीसी छात्रों की मानसिकता प्रभावित हो रही है। ऐसी राजनीति किसी भी समुदाय के लिए अच्छी नहीं है। भले ही कुछ नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करें, लेकिन लोग वास्तविक स्थिति को समझेंगे।

प्रोफेसरों के पद भरने की अनुमति दीः फडणवीस

कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती में चल रही देरी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने 80 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हुई है। आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं और ये पद जल्द ही भर दिए जाएंगे। फडणवीस ने कहा कि डीजे बजाने में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लोगों में इस प्रथा को छोड़ने के लिए जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हडपसर क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण किया

अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके यातायात की समस्या का समाधान करें: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुणे। शहर में दिनों-दिन बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए, सरकार सड़कों के चौड़ीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री अजीत पवार ने कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात की समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके हल किया जाना चाहिए।

पवार ने खराडी से केशवनगर पुल के निर्माण कार्य के साथ-साथ मुंधवा चौक और हडपसर गाडी ताल पर यातायात की समस्या के समाधान के लिए स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक चेतन तुपे, पुणे नगर निगम आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

पवार ने कहा कि खराडी से केशवनगर पुल के निर्माण कार्य में अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इस पुल से

चंदननगर, केशव नगर, खराडी क्षेत्रों के नागरिकों को यातायात की समस्या से राहत मिलेगी, इसलिए इसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। पवार ने आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र के नागरिक पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, कानून-व्यवस्था, बस व्यवस्था आदि से संबंधित विभिन्न मांगें रखेंगे और उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

पवार ने सुझाव दिया कि पुणे महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, पीएमपीएल और जनप्रतिनिधियों को एक बैठक आयोजित करनी चाहिए और मुधनवा चौक और हड़पसर गडीताल में यातायात की समस्या के समाधान के लिए सभी आवश्यक विकल्पों पर विचार करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

मराठा आरक्षण न मिलने से दुखी था किसान, जहर खाकर कर ली खुदकुशी

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले से मराठा आरक्षण न मिलने के चलते आत्महत्या का मामला सामने आया है. यहां एक किसान ने जहरीली दवा खाकर अपनी दे दी है. आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर ये तीसरी मौत हुई है. घटना के बाद से ही मृतक किसान के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि मृतक किसान आरक्षण न मिलने के कारण काफी परेशान चल रहा था. इस बीच डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया.

बीड जिले के अहेर धनोरा के रहने वाले 39 साल के संतोष अर्जुन वाले ने मराठा आरक्षण न मिलने का दुख जताते हुए जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली. संतोष वाले ने कई मराठा आरक्षण आंदोलनों में भाग लिया था. स्कूल में पढ़ रहे उनके दो बच्चे बार-बार कहते थे कि आने वाला समय कठिन होगा क्योंकि उन्हें मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है. वह लगातार निराश रहते थे. इसी दौरान 2 सितंबर को उन्होंने जहरीली दवा खा ली.

किसान ने किया सुसाइड

इस बात की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया. आनन-फानन में उन्हें बीड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद कई दिनों तक उनका वहां गंभीर हालत में इलाज चला. इस बीच उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. साथ ही इलाके में गम का माहौल है. मृतक किसान के परिवार में पत्नी पल्लवी वाले, दो छोटे बच्चे, एक भाई, माता-पिता और भाई-बहन हैं.

मराठा आरक्षण की मांग हो रही तेज

आपको बता दें कि इसके अलावा मराठा आरक्षण की मांग के बीच बंजारा समुदाय ने रिजर्वेशन की मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है. इस बीच आंदोलन की मांग के लेकर एक बंजारे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या अपनी जान दे दी है. मृतक के परिजनों का कहना है कि आरक्षण की मांग को लेकर उनके बेटे ने आत्महत्या की है. युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आरक्षण का जिक्र किया है.

शरद पवार बोलेः मराठाओं को आरक्षण देने से एससी, एसटी और ओबीसी पर असर पड़ेगा, सामाजिक एकता कमजोर कर रही सरकार

नासिक।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की महा युति सरकार राज्य की सामाजित एकता को कमजोर कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस स्थिति का मुकाबला करने की अपील की। पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने दावा किया कि राज्य सरकार में फूट डालने का काम कर रही है।

शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जनजातीय और बंजारा समुदाय से जुड़े कई सगंठन प्रदर्शन की चेतावनी दे रही हैं। ये संगठन मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण को लेकर जारी किया गया सरकारी आदेश (जीआर) वापस ले। इन संगठनों का कहना है कि हैदराबाद गजट को लागू करके मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण देने से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी वर्गों पर बड़ा असर पड़ेगा।

'पहली बार जाति-समुदाय के आधार पर बनी समिति'

पवार ने कहा कि हैदराबाद गजट में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां (वीजेएनटी) और बंजारा समुदाय को अनुसूचित

जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया गया है और अब ये समुदाय भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर लेकर जो कैबिनेट उप समितियां बनाई गई हैं, उनमें केवल उन्हीं दोनों समुदायों के मंत्री शामिल हैं। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हुई है कि किसी सरकारी समिति का गठन जाति और समुदाय के आधार पर किया गया है।

'मनोज जरांगे के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं'

शरद पवार ने आरोप लगाया, लगता है सरकार समस्याओं को सुलझाना ही नहीं चाहती। वह सामाजिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हमें इसका डटकर विरोध करना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई राजनीतिक कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। सामाजिक एकता और भाईचारे से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

मीडिया से बातचीत में पवार ने कहा कि उनका कार्यकर्ता मनोज जरांगे या उनके आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है।

'राज्य में जाति-समुदाय के आधार पर गहरी खाई'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जरांगे के आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर मेरी कोई टिप्पणी जरूरी नहीं है। यह आरोप निराधार है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। पवार ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में जाति और समुदाय के आधार पर गहरी खाई है और यह चिंता की बात है। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि वह अपने किसान मोर्चे को मजबूत करें और खेती-किसानी को नुकसान न हो, इसके लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाएं।

'भारत को अपनी शर्तों पर चला रहा अमेरिका'

पवार ने दावा किया कि पिछले आठ महीनों में राज्य में 1,186 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 700 मौतें विदर्भ और 820 मराठवाड़ा में हुई हैं। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला किया और कहा कि भारत की विदेश नीति ऐसी हो गई है कि अब देश के पास कोई दोस्त नहीं बचा है। उन्होंने कहा, हमारे सभी पड़ोसी देश अब हमारे खिलाफ हो गए हैं और अमेरिका अब भारत को अपनी शर्तों पर चला रहा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया शरद पवार पर पलटवार

शरद पवार के इस आरोप पर कि राज्य की सामाजिक एकता कमजोर हो रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा, हर कोई जानता है कि पवार साहब किस चीज के लिए मशहूर हैं। जब वो 'एक्स' कहते हैं तो समझिए उसका मतलब 'वाई' होता है। वो बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में और क्या कह सकता हूं?

उद्धव ठाकरे के बयान पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस से गठबंधन को लेकर साधा निशाना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दुबई में होने वाले इस मैच को राष्ट्रभावनाओं का अपमान बताया और लोगों से अपील की कि वे यह मैच न देखें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सिंदूर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेंगी, ताकि सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई जा सके।

भाजपा ने उद्धव पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप

रविवार को भाजपा ने उद्धव पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने कहा, 'उद्धव ठाकरे भाजपा पर देशभक्ति का दिखावा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि मुंबईकरों का सिंदूर क्या कम है? 26/11 हमले के बाद सेना तैयार थी, पर उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस डर गए, जिससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ा। आज वही कांग्रेस उद्धव की सबसे पसंदीदा पार्टी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान को उसके घर में सबक सिखाया, उन्हें उद्धव नापसंद करते हैं।'

'26/11 हमले के बाद उद्धव चुप क्यों रहे?'

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी पूछा कि 26/11 हमले के बाद उद्धव चुप क्यों रहे और क्या उनमें राहुल गांधी से सवाल पूछने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान ने देशभर में साजिशें रचीं, और मुंबई भी उसका शिकार बनी। भाजपा प्रवक्ता ने

कांग्रेस को 'पाकिस्तान समस्या की जड़' बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, और अब वही कांग्रेस उद्धव की सबसे करीबी सहयोगी पार्टी है।

संजय राउत पर भी भाजपा नेताओं का हमला

वहीं भाजपा मीडिया सेल प्रमुख नवनाथ बान ने उद्धव और उनके करीबी नेता संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका राष्ट्रवाद दिखावटी है। 'अगर उद्धव सचमुच मैच का विरोध करते हैं, तो पहले अपने ही सहयोगी मिलिंद नार्वेकर से इस्तीफा दिलवाएं, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल में हैं। असली राष्ट्रवाद घर से शुरू होना चाहिए।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उद्धव की पार्टी को पाकिस्तान का इतना ही विरोध है, तो उन्हें मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे भेंडी बाजार और मालवणी में जाकर पाक समर्थकों का सामना करना चाहिए, न कि सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध करना चाहिए।

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सताम ने भी उद्धव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर उनकी और नार्वेकर की तस्वीर साझा की और सवाल उठाया कि उद्धव ने कभी नार्वेकर के विचारों पर सवाल क्यों नहीं किया।

उद्धव ठाकरे ने क्या दिया था बयान

उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने पिता और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा था, 'जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून भी साथ नहीं बह सकते। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए।' बता दें कि सरकार की नई खेल नीति के अनुसार, भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स जैसे बहुपक्षीय आयोजनों में उसका सामना करता रहेगा।

नासिक में दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से चेन लूटकर फरार हुए बदमाश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नासिक । महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां दिनदहाड़े दो अज्ञात बदमाश एक घर में घुसे और महिला को निशाना बनाते हुए लूटपाट की. बदमाश महिला के गले से सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गए. यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरोपी ने महिला के साथ की छीनाझपटी

जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर करीब 4 बजे की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो अज्ञात बदमाश पहले महिला की मदद करने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर घर के पास तक आए फिर महिला का बाहर रखा सामान अंदर रखवाए और पीने के लिए पानी मांगा. पानी पीने के बाद एक आरोपी ने महिला के साथ छीनाझपटी की. महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उन्होंने गले से चेन झपट ली और तुरंत बाहर भाग निकले. पूरी वारदात कुछ ही सेकंडों में पूरी हो गई.

घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश वहां से दूर निकल चुके थे. आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है.

घटना के बाद लोगों में दहशत

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है. इस घटना ने इलाके के लोगों में दहशत फैला दी है. लोगों का कहना है कि बदमाश अब दिनदहाड़े घरों में घुसकर वारदात कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

ट्रक ड्राइवर का किडनैप! अब सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां विवादों में

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ समय पहले वहगलत सर्टिफिकेट की वजह से चर्चा में आई थी और उनकी मां भी सुर्खियों में आई थी. पूजा की मां द्वारा बंदूक लेकर उन पर हमला करने का एक वीडियो सामने आया था. उसके बाद, एक और घटना सामने आई है. मुंबई के ऐरोली से एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने का आरोप उनकी मां पर लगा है. यह ड्राइवर अब पुणे के चतुश्रृंगी इलाके में पूजा खेडकर के घर पर मिला है।

सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने सोशल साइट एक्स पर इस मामले की जानकारी दी है. विजय कुंभार ने अपने पोस्ट में कहा, 'विवादित और निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां का एक और कृत्य सामने आया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.'

पूजा खेडकर की मां पर लगे आरोप

उन्होंने लिखा कि 13 सितंबर 2025 को शाम करीब 7 बजे मुलुंड से ऐरोली रोड पर ऐरोली इलाके के सिग्नल पर तुर्भे एमआईडीसी नवी मुंबई के निवासी प्रह्लाद कुमार (उम्र 22 साल) अपना मिक्सर ट्रक लेकर जा रहे थे, तभी कार नंबर श्ए 12ऊ 5000 ने मिक्सर को टक्कर मार दी और कार में सवार दो लोगों ने उन्हें जबरन अपनी कार में डालकर अगवा कर लिया. रबाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला दर्ज किया गया है।

अपहृत चालक को बचाया गया

विजय कुंभार ने अपनी पोस्ट में कहा, 'अपराध की जांच करते हुए, सहायक पुलिस निरीक्षक खरात कार का पता लगाने पुणे गए और उसे चतुश्रृंगी इलाके में विवादास्पद आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के घर पर पाया।

एपीआई खरात और उनकी टीम ने अपहृत ड्राइवर को वहां से छुड़ाया. जांच के दौरान, पूजा खेडकर की मां ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और दरवाजा नहीं खोला. पुलिस ने उन्हें रबाले पुलिस स्टेशन आने का निर्देश दिया है और आगे की जांच जारी है।

सम्पादकीय

वर्दी में पुलिस का धर्म सिर्फ कानून है निष्पक्षता असली पहचान; सुप्रीम कोर्ट को क्यों देनी पड़ी यह नसीहत?

किसी भी मौके पर जब पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, तब उम्मीद की जाती है कि वह बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात किए या दबाव में आए बगैर पीड़ित पक्ष के हक में अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। इस क्रम में किसी भी हाल में उसके ऊपर धर्म या जाति से जुड़े आग्रह हावी नहीं होंगे और वह सिर्फ न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पुलिस महकमे से जुड़े लोग कई बार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते।

ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिनमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे या किसी खास तबके या समूह के खिलाफ पक्षपात करने के आरोप भी लगे। जबकि कानून की वर्दी पहनने के साथ ही व्यक्ति एक दायित्व से बंध जाता है कि उसे हर हाल में न्याय के पक्ष में खड़ा होना है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में कानून की सीमा में सभी स्तर पर सहयोग करना है। अफसोस की बात है कि इस तरह के जिन दायित्वों को याद रखना खुद पुलिस महकमे और उससे जुड़े लोगों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए कई बार अदालतों को हस्तक्षेप करना और याद दिलाना पड़ता है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अकोला में 2023 में हुए दंगे के एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पुलिस को नसीहत दी कि निष्पक्षता ही उसका असली दायित्व है। अदालत ने कहा कि जब एक बार कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है, तो उसे अपने निजी झुकाव, धर्म, जाति या किसी अन्य प्रकार के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर कानून के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उसे अपने पद और अपनी वर्दी से जुड़े कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए।

हालांकि ये अपेक्षाएं पुलिस महकमे से जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के काम करने और सोचने के तरीके में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शामिल होनी चाहिए, निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में काम करना उसके व्यक्तित्व और विचार का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। मगर पहले तो किसी आम नागरिक के सामने पुलिस पर अपने खिलाफ पूर्वाग्रह बरतने और पक्षपात करने का आरोप लगाने की नौबत आती है, फिर शीर्ष अदालत को यह बताना पड़ता है कि पुलिस का काम किसी धर्म या जाति पर आधारित भेदभाव के बिना कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच करना है।

सांप्रदायिक दंगों के दौरान कार्रवाई और जांच के संदर्भ में पुलिस पर धार्मिक पहचान के आधार पर पक्षपात बरतने के आरोप अक्सर सामने आए हैं। कमजोर या वंचित जातियों के लोगों के खिलाफ अपराधों के मामले में भी पुलिस पर रसूख वाले वर्गों के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं।

इस लिहाज से देखें तो अकोला दंगे से संबंधित मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह महाराष्ट्र सरकार को विशेष जांच दल गठित करने और उसमें हिंदू तथा मुसलिम समुदायों के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया है, वह एक तरह से पुलिस की कार्यशैली में छिपे पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक दंगे की जांच के लिए दोनों समुदायों के अफसरों को शामिल करने का आदेश दिया है।

यह याद रखने की जरूरत है कि वर्दी पहनते ही किसी व्यक्ति के साथ यह दायित्व अनिवार्य रूप से जुड़ जाता है कि कानून और न्याय के पक्ष में उसे अपने भीतर के जातिगत या धार्मिक पूर्वाग्रहों और बाहर के दबावों से मुक्त होकर काम करना है।

राष्ट्र की पहचान से विश्व की साझी भाषा तक हिन्दी की शक्ति

हर वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाने वाला हिन्दी दिवस उस गौरव की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, जब हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। यह दिवस हिन्दी की समृद्धि, स्वीकार्यता, रचनात्मकता और वैश्विक विस्तार का उत्सव है। निरंतर बढ़ती हिन्दी शक्ति आज न केवल भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य को आकार देती है बल्कि विश्व मंच पर भी अपनी प्रगाढ़ छाप छोड़ रही है। आज दुनियाभर में हिन्दी चाहने वालों, बोलने या पढ़ने-समझने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हिन्दी को लेकर भारतीय और विदेशी विद्वानों, साहित्यकारों तथा विभूतियों का आदर भाव वर्षों से रहा है।

डा. फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने हिन्दुस्तानी संस्कृति को आत्मसात किया, हिन्दी को गृहिणी की संज्ञा देते हुए कहा था कि यह भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। संस्कृत को तो वे मां मानते थे और अंग्रेजी को नौकरानी। इसी तरह आयरिश प्रशासक जॉन ग्रियर्सन ने हिन्दी को संस्कृत की बेटियों में सबसे सुंदर और शिरोमणि बताया। ऐसे तमाम उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि हिन्दी, शब्द और विचार के धरातल पर विभिन्न भाषाओं से जितनी आत्मीयता रखती है, उतनी ही भारत के जनमानस से जुड़ी है लेकिन दुखद है कि आज भी पुनरुत्थानवादी मानसिकता वाले कुछ लोग हिन्दी की व्यापकता, समृद्धि और ताकत को नजरअंदाज करते हैं और संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को स्थान नहीं मिलने की बात पर कुतर्क करके उसके वैश्विक पक्ष को कमतर आंकते हैं। हालांकि ऐसी नकारात्मक चर्चाओं से न हिन्दी का कुछ भला हो सकता है, न ही उसका अस्तित्व डिग सकता है। तथ्य यही है कि आज विश्वभर में हिन्दी बोलने वालों का आंकड़ा करोड़ों में है और यह

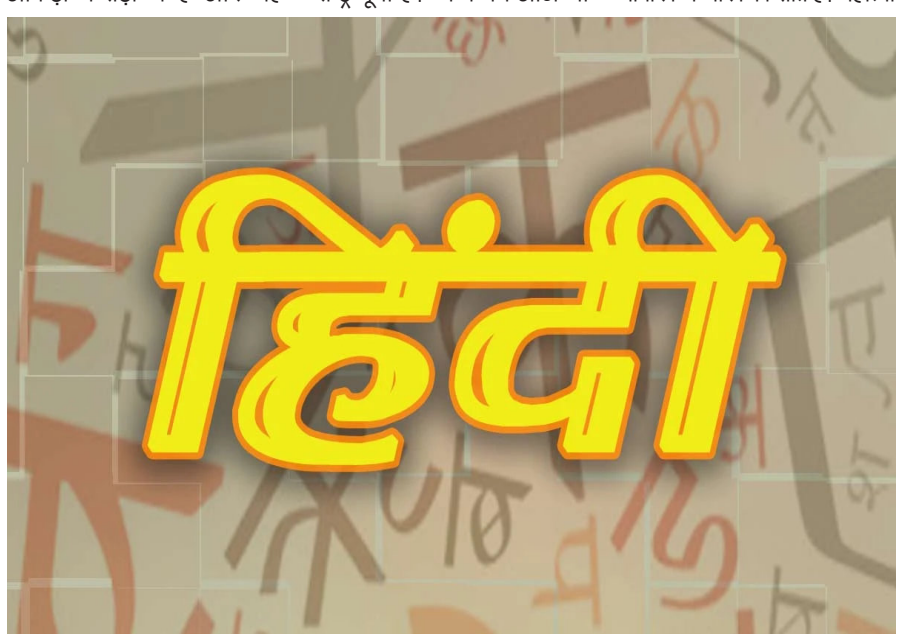

निरंतर बढ़ रहा है।

हिन्दी की ताकत को जानना हो तो उसके सांस्कृतिक, भावनात्मक और रचनात्मक विस्तार को देखना होगा। मातृभाषा का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के मन की पीड़ा का सबसे अच्छा समाधान है। महापुरुषों, विद्वानों और नेताओं ने समय-समय पर हिन्दी भाषा के महत्व को रेखांकित किया है। पुरुषोत्तमदास टंडन मानते थे कि जीवन के हर क्षेत्र में हिन्दी अपनी भूमिका निभाने में समर्थ है। महात्मा गांधी ने हिन्दी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संवाद व जनसंपर्क का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। उनके शब्द थे कि सम्पूर्ण भारत की पारस्परिकता के लिए ऐसी भाषा चाहिए, जो जनता का बड़ा भाग जानता-समझता हो। गांधीजी कहते थे, 'दिल की कोई भाषा नहीं है, दिल से दिल संवाद करता है और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।' ये कथन आज भी वैसी ही सार्थकता के साथ जीवंत हैं। अमेरिकी चिकित्सक वॉल्टर चेनिंग तो यह मानते थे कि विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र की शिक्षा एवं प्रशासन की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। माखनलाल चतुर्वेदी और राहुल सांस्कृत्यायन ने हिन्दी को देश और भाषा की विरासत, सांस्कृतिक धरातल और अधिष्ठान के रूप में देखा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने तो यहां तक कहा कि राष्ट्रीय एकता का बंधन केवल हिन्दी ही जोड़ सकती है।

हिन्दी की ऊर्जा और आत्मबल का उदाहरण महात्मा गांधी के हिन्दी प्रेम का एक प्रसंग भी है। सन् 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में भाषण दिया था। गांधीजी ने तिलक को स्पष्ट समझाया कि देशवासियों के साथ अपनी ही भाषा में संवाद ही सही अर्थों में दिलों तक पहुंच सकता है। यह भावप्रवण संवाद भारत के हर नागरिक के गौरव का स्रोत है। महात्मा गांधी ने विविध अवसरों पर हिन्दी को राष्ट्र की आत्मा कहा था। आज हिन्दी का विस्तार भारत तक सीमित नहीं रहा। कई देशों में हिन्दी लोगों के दिलों में बसती है, जहां की स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी भी संगठित रूप से बोली जाती है। दुनियाभर में सैंकड़ों विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, शोध केंद्रों और अनगिनत प्लेटफॉर्म्स पर हिन्दी पढ़ाई जाती है, शोध होती है और यह वहां अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की भाषा बन चुकी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 75 करोड़ लोग हिन्दी बोलते समझते हैं और एथ्नोलॉग जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषायी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विश्वभर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है।

हिन्दी का वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव भी आश्चर्यचकित करता है। भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे दुनियाभर में 'बॉलीवुड' के नाम से जाना जाता है, हर साल करीब 1500 फिल्में हिन्दी में बनाता है। ये फिल्में भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, खाड़ी देशों सहित अनेक देशों में देखी जाती हैं। हिन्दी फिल्मों, गीतों, साहित्य और कला का प्रभाव विदेशी मंचों, सांस्कृतिक समारोहों, मीडिया एवं एफएम चैनलों तक फैला हुआ है। यूएई में हिन्दी एफएम चौनल स्थानीय लोगों की खास पसंद बन चुके हैं। हिन्दी फिल्म अभिनेता, निर्माता व कलाकार विदेशों में शो आयोजित करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और हिन्दी भाषा का विस्तार होता है। जहां-जहां भारतवंशी बसे हैं, वहां हिन्दी विशेष सम्मान के साथ जीवंत है। यह यथार्थ हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।

वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, तकनीकी और प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनियों ने हिन्दी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। भारत में 80 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता हिन्दी में सामग्री अपनाते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिन्दी की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है और इसका प्रसार इतनी गति से हो रहा है कि कुछ ही वर्षों में हिन्दी इंटरनेट की प्रमुख भाषा बन सकती है। हिन्दी की संवैधानिक सुरक्षा भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के तहत निश्चित है। यह धाराएं हिन्दी के प्रचार-प्रसार, स्वीकार्यता और संरक्षण का मजबूत आधार हैं। यह न केवल भारत की आधिकारिक भाषा है बल्कि सम्पर्क भाषा, प्रशासन और विधि के क्षेत्र में इसका प्रयोग निर्णायक रूप से हो रहा है। भारत के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सांस्कृतिक आयोजनों में हिन्दी को सम्मानपूर्वक अपनाया गया है। विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना, हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दिलवाने की पहल और डिजिटल क्षेत्र में हिन्दी सशक्तीकरण, ये सभी कदम हिन्दी के वैश्विक मंच पर सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए हैं।

कुल मिलाकर, हिन्दी दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह हमारी संस्कृति, भाषायी आत्मसम्मान और राष्ट्रीय एकता का दिन है। इस दिन हर भारतीय को यह संकल्प लेना चाहिए कि हिन्दी को रचनात्मक, सुंदर और समृद्ध बनाए रखने में अपना योगदान दे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का सपना केवल राजभाषा का प्रतिष्ठापन नहीं था बल्कि भारत की आत्मा, उसकी विविधता और सांस्कृतिक गौरव की अभिव्यक्ति थी, जिसे हिन्दी ने बखूबी आकार दिया है। हिन्दी भाषा की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रतिष्ठा आज न केवल भारत की बल्कि विश्व संस्कृति की सबसे मजबूत और सुंदर कड़ी बन चुकी है। इसलिए, हिन्दी दिवस के अवसर पर यही प्रेरणा लें कि जीवन के हर क्षेत्र में हिन्दी का उत्कर्ष हो, इसकी भाषायी, सांस्कृतिक, साहित्यिक और तकनीकी शक्ति निरंतर बढ़ती रहे और आगामी पीढ़ियां हिन्दी को न केवल संवाद का बल्कि वैश्विक अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावशाली माध्यम बनाएं।

तरक्की की दौड़ में हम खुद ही काट रहे हैं अपनी जड़ें, इंसानियत और कुदरत को भी नहीं छोड़ा

आर्थिक विकास की अंधी होड़ में न मानवीय संवेदनाएं बच रही हैं, न प्रकृति का संतुलन। प्रकृति अब चेतावनी देने के बजाय सीधा हिसाब चुकता कर रही है। आज देश में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन इसी रफ्तार में इंसानियत और प्रकृति, दोनों पिछड़ते जा रहे हैं। रोज आत्महत्या और हिंसा की खबरें समाज की मानसिक थकान का सबूत हैं, तो बादल फटना और पशुओं की आक्रामकता प्रकृति के असंतोष के संकेत।

सवाल यह है कि क्या हम आज सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं और आंख मूंदकर विकास के नाम पर अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं! देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन रोज सामने आने वाली आत्महत्या और हत्या की खबरें यह संकेत दे रही हैं कि नागरिक चेतना और मनोबल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।

अतीत की यादें और भविष्य की चिंता छोड़िए; हर पल को जीना ही बुद्धिमानी है, जो आज है वही असली जीवन

आए दिन होते रिश्तों के कत्ल, बलात्कार, छोटी-छोटी बातों पर हत्या और आत्महत्या- ये सब संकेत हैं कि मनुष्य मानसिक रूप से थकता जा रहा है और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ चुका है। संवेदनशीलता लगातार घट रही है, सहनशीलता खत्म हो चुकी है। मगर एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ बढ़ती जा रही है, जो तनाव, अकेलापन, रिश्तों में खटास और अविश्वास के रूप में दिखाई देती है। इसके कारण समाज के ताने-बाने को बचाना तो दूर, परिवार को बचा पाना भी मुश्किल हो गया है।

आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आय, कारोबार और उत्पादन को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। इस दौड़ में हम उन नैतिक जिम्मेदारियों और प्राकृतिक संतुलन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो जीवन की असली नींव हैं। हम भूल रहे हैं कि यह जीवन कोई 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देन नहीं है, जिसमें कोई चिप लगा कर अपने अनुसार नियंत्रण किया जाए। यह प्रकृति की देन है और जो उसके दिए जीवन के मूल और मोल को नहीं समझेगा, प्रकृति वह जीवन सूद समेत वापस ले लेगी। फिर क्यों आज मनुष्य सब जानते हुए भी अनजान बन रहा है?

हाल में लावारिस कुत्तों का मुद्दा इस उपेक्षा का एक उदाहरण है। कुत्ते प्रकृति में विभिन्न आवासों-

जंगल, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र में रहने के लिए बने हैं, सड़कों पर भटकने के लिए नहीं। मगर मानव ने उनके प्राकृतिक घर छीनकर उन्हें 'आवारा' बना दिया। परिणामस्वरूप वे आक्रामक होते जा रहे हैं। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस पर विशेष कमेटी बनाई गई। यही स्थिति पर्यावरण के साथ भी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने की घटनाएं इसकी चेतावनी हैं। पहाड़ों को काटकर और नदियों का अस्तित्व मिटाकर हमने अपने लिए घर तो बना लिए, लेकिन प्रकृति ने उसी नदी को विनाश के रूप में लौटा दिया।

आज पहले के समय से तुलना करें तो परिस्थिति बिल्कुल उलट गई है। उस समय इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता था। दोनों के बीच एक सामंजस्य बना हुआ था। हमारे बुजुर्ग पेड़-पौधों, ऋतुओं, नदियों और पशुओं की पूजा करते थे। वे भले पढ़े-लिखे कम थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि जो कुछ हमें मिल रहा है, वह प्रकृति की ही देन है। अगर इसके प्रति भाव बदल गया तो तबाही तय है। गांवों में लोग सादा जीवन जीते थे और सामूहिकता पर जोर देते थे। संवेदनाएं और जिम्मेदारियां भी साझा होती थीं। गली-मोहल्ले के लोग भी रिश्तों से जुड़े होते थे, जिससे भाईचारे का संदेश मिलता था। आज सब उलट है।

गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। बढ़ती इच्छाओं के चलते अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, पशुओं से जंगल छीने जा रहे हैं, नदियों का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। रिश्तों का रोज खून हो रहा है। एकजुटता, विश्वास और सामूहिकता खत्म होने के कगार पर हैं। इसका खामियाजा हमें त्रासदी के रूप में भुगतना पड़ रहा है. नदियों के खत्म होने से बाढ़, भूकम्प और बादल फटने जैसी घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। पशुओं से जंगल छीनकर उन्हें सड़कों पर रहने को मजबूर किया गया है और उनका आक्रोश अब इंसानों पर उतर रहा है। कई पक्षी और पशु प्रजातियां विलुप्त होने के रास्ते पर हैं। गौरैया, जो कभी हर आंगन में दिखती थी, अब शहरों से गायब है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। कभी भीषण गर्मी, तो कभी अनियंत्रित बारिश और कभी असामान्य सर्दी। बढ़ता जलवायु परिवर्तन हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। अपनों का ही कत्ल आम हो गया है। पहले गांव सामूहिकता बोध और परिवार की तरह होते थे, आज सामूहिक बलात्कार की खबरें आम हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने केवल इंसानियत को ही कमजोर नहीं किया, बल्कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ पर्यावरणीय संकट बनकर सीधे-सीधे हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर असर डाल रहा है।

स्पष्ट है कि चाहे वह पशुओं का घर छीनना हो, प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करना हो या इंसानियत को ताक पर रखना हो- प्रकृति और जीवन का चक्र हमेशा जवाब देता है। अगर अभी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत और नैतिक मूल्यों के नाम पर हमारा दिवालिया होना तय है। सचेतन अनदेखी का हासिल शायद ज्यादा भयावह हो सकता है।

क्या डिजिटल इंडिया सचमुच सबके लिए है? हाशिये पर खड़े लोग क्या ई-गवर्नेंस में अब होंगे शामिल?

कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। मामला तेजाब हमले के एक पीड़ित और दृष्टिबाधित व्यक्ति की ओर से दायर याचिकाओं से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि देश के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तमाम योजनाएं और सेवाएं ऐसी हैं, जिनमें बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं का लाभ उन जैसे लोग इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि चेहरे के घावों, चोटों के निशान या दृष्टिबाधित होने पर तकनीकी बाध्यताओं के कारण वे अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं। चूंकि इन लोगों की डिजिटल पहचान अंकित नहीं हो पाती है या फिर डिजिटल पहचान की जांच में ये लोग नाकाम रहते हैं, इसलिए बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं में उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

ऐसे में उनके साथ सतत डिजिटल सेवाओं के मामले में भेदभाव हो रहा है। सर्वोच्च अदालत का फैसला अपने आप में काफी तार्किक और सुविचारित है। मगर अभी भी हमारे देश और समाज में कई चीजें ऐसी हैं, जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं। जैसे कि तकनीक की सही जानकारी न होना और भाषा की बाध्यता।

इस कारण बहुत से लोग डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाना तो दूर, उल्टा इसके जरिए फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। हाल में ऐसी कई रपट सामने आई हैं, जिनमें तथ्यों पर आधारित दावा किया गया है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वे तकनीक के कम जानकार हैं, लेकिन बैंकिंग आदि तमाम सहूलियतें पाने के लिए उन्हें विवशता में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है।

यह मामला सिर्फ तकनीकी दक्षता का नहीं है, बल्कि इससे एक समावेशी समाज का पहलू भी जुड़ा हुआ है। इस नजरिए से देखें तो दुनिया में साढ़े पांच अरब से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हम तकनीकी रूप से समर्थ मान सकते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक आबादी का करीब 68 फीसद है। इनमें से लगभग 5.24 अरब लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया की 64 फीसद आबादी है।

इस संदर्भ में भारत को देखें तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 87 करोड़ थी और इसमें प्रतिवर्ष करीब आठ फीसद की बढ़ोतरी हो रही है। इस आधार पर वर्ष 2025 के अंत तक देश में नब्बे करोड़ लोग इंटरनेट का सक्रिय इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इससे बाहर की आबादी या यों कहें कि उन लोगों की स्थिति क्या है, जो विभिन्न कारणों से डिजिटल तंत्र से नहीं जुड़ पाए हैं।

अगर हम भारत की आबादी 1.40 अरब मानें तो अभी भी करीब पचास करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डिजिटल तौर पर शेष देश से कटे हुए हैं। इनमें भी उन लोगों की स्थिति और भी विकट है, जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल साधनों के इस्तेमाल में पीछे छूट जाते हैं। डिजिटल तंत्र के इस असाधारण पहलू की तरफ तब नजर गई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।

शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं की विस्तार से जांच की और यह पाया कि याचिकाकर्ताओं में से एक तेजाब हमले का पीड़ित व्यक्ति अपनी आंखें झपकने में अक्षम है, जबकि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टिबाधित है। इस वजह से इन दोनों का बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है।

दृष्टिबाधित याचिकाकर्ता ने तर्क दिए थे कि केवाईसी प्रक्रिया के दौरान सेल्फी लिए जाने, लिखित हस्ताक्षर करने, शीघ्रता से ओटीपी पढ़ने और उसे सही स्थान पर भरने जैसी अड़चनें उनके जैसे लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। वहीं, तेजाब पीड़ित व्यक्ति ने दावा किया था कि केवाईसी की प्रक्रिया में कैमरे में देखकर पलकें झपकाने का नियम उन जैसे लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने इन तकनीकी बाध्यताओं का हवाला देते हुए केवाईसी के नियमों में बदलाव की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने सभी को गरिमा के साथ जीने और आजीविका कमाने के अधिकार की रोशनी में देखा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और सभी संबंधित पक्षों को केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यह दायित्व सरकार का है कि वह समाज में हाशिये पर पड़े, वंचित, कमजोर और दिव्यांग वर्गों को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करे।

इन निर्देशों के तहत अदालत का उद्देश्य देश में नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया- आधार, आनलाइन सेवा वितरण मंच और नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल प्रगति की लहर के बीच एक महत्त्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करना है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह पहलू डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तकनीकों को अपनाने से जुड़ा है, जिनमें अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि क्या ये वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समावेशी और सुलभ हैं।

अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बैंकिंग ही नहीं, बल्कि राशन, चिकित्सा और शिक्षा समेत तमाम तरह की सुविधाएं और सेवाएं किसी न किसी रूप में डिजिटल पहचान के स्रोतों से जुड़ गई हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी शारीरिक अक्षमता, चोट अथवा विकृति के कारण इससे संबंधित प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाता है, तो वह लगभग सभी सेवाओं और सुविधाओं से वंचित हो जाता है।

इस मामले में शीर्ष अदालत का यह कहना भी प्रासंगिक है कि हर स्तर पर डिजिटल खाई को भरना अब केवल नीतिगत मसला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक जरूरत बन गया है, ताकि प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वायत्तता और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी करने का अवसर मिल सके। इस निर्णय का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें नागरिकों की डिजिटल पहचान करने वाली सरकारी और निजी संस्थाओं (जैसे के निजी बैंकों) पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि कोई भी नागरिक किसी शारीरिक अक्षमता, विकृति अथवा दिव्यांगता के कारण डिजिटल रूप से कहीं पिछड़ न जाए।

इस तरह से कहा जा सकता है कि यह फैसला देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने का भी काम करेगा। चूंकि इससे सभी नागरिकों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक समान मौके मिलेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी काफी गंभीर है। ऐसे लोग जिन्हें मजबूरी में डिजिटल बैंकिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, वे साइबर धोखाधड़ी के आसान शिकार बन रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग और केवाईसी आदि के लिए कागज आधारित पारंपरिक पुष्टिकरण की व्यवस्था और वीडियो-आधारित केवाईसी की प्रक्रिया आज के समय की जरूरत है। इसी तरह भाषायी समस्या के समाधान के लिए अनुवाद तथा आडियो को केवाईसी का हिस्सा बनाना चाहिए, जबकि दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि आधारित प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए।

16 नवंबर को सर्व वैश्य एवं व्यापारी समाज का विशाल सम्मेलन लखनऊ में होगा आयोजित

व्यापारियों के हित में समर्पित है सरकार : बृजेश शुक्ला

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। वैश्य एवं व्यापारी समाज की बैठक आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने किया इस अवसर बैठक के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्तर मंत्री बृजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार व्यापारियों के हित में समर्पित है जो व्यापारियों के हित में क़दम उठा रही है और सरकार गुंडों और माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम किया है जिससे आज व्यापारी पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर व्यापार कर रहा है और कहा कि व्यापारियों के द्वारा मांग किए जाने पर मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी पर टैक्स कम कर देने से बिक्री बढ़ेगी और व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

आगे कहा कि 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में विशाल सम्मेलन सर्व वैश्य समाज और व्यापारी समाज का आयोजन किया जाएगा जिसको हम सभी को मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना और सरकार के द्वारा व्यापारियों के हित में किए गए कार्य को बताना है।

मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी पर और सुधार करने को लेकर अपना सुझाव दिया और जिला प्रशासन के द्वारा गाड़ियों पर जबरन किए जा रहे चालान को समाप्त करने को लेकर अपनी विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री कमलेश केसरवानी ने कहा कि सर्व वैश्य सम्मेलन को हमें पूरी ताकत के साथ सफल बनाना है। संचालन राजेश केसरवानी एवं राजकुमार केसरवानी ने किया और समापन गौरव गुप्ता ने किया।

इस अवसर व्यापारी एवं वैश्य समाज के नेता प्रमिल केसरवानी रमेश चंद्र केसरवानी, कांत केसरवानी, तीर्थराज केंसरवानी, धर्मेंद्र केसरवानी, अनिल केसरवानी, अशोक कुमार गुप्ता, राजेन्द्र केसरवानी हिमांशु खरबंदा, राजीव कृष्ण श्रीवास्तव, सुनील केसरवानी पप्पू कटरा, अजय कुमार कमलेश केशरवानी, शत्रुघ्न जायसवाल, शिव शंकर आदि सैकड़ो व्यापारी उपस्थित रहे।

दहेज उत्पीड़न के मामले में नंद और नंदोई के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़खानी के मामले में नंद दीक्षा कटियार व आकांक्षा कटियार तथा नंदोई बिजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता स्वाती कटियार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ा था, जिसमें नंद-नंदोई ने केस कार्यवाही को चुनौती दी थी। पत्नी स्वाती कटियार ने अपने पति शिवम कटियार, सास, नंद, नंदोई सहित अन्य पर दहेज मांगने, मारपीट और छेड़खानी का मामला थाना गोविंदनगर, कानपुर में दर्ज कराया था।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने प्रभा कटियार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस में कहा कि घटना वाले दिन नंद दीक्षा कटियार इलाज कराने ससुराल आई थीं, जहाँ उनके जीजा बृजेंद्र प्रताप सिंह व बड़ी बहन आकांक्षा कटियार मौजूद थे। 27 मई 2024 को दीक्षा, आकांक्षा व नंदोई विदेश मलेशिया चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वाती कटियार ने पूरे परिवार को झूठे दहेज

उत्पीड़न के मामले में फंसाया और देवर पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि स्वाती कटियार बार-बार ससुराल की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाती रहीं। विवाद बढ़ने पर सास प्रभा कटियार ने न्यायालय में चल-अचल संपत्ति से बेदखली कराई, जिसके बाद स्वाती कटियार और उनके पति अलग रह रहे थे। वहीं से उन्होंने फिर से संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाया और उत्पीड़न किया। अंततः उन्होंने पुलिस में शिकायत कर सुलह के बाद फिर से झूठे आरोप लगाए।

हाई कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर नंद और नंदोई के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह आदेश पारिवारिक विवादों में झूठे आरोपों से बचाव का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

ट्रिपल आईटी के पूर्व निदेशक डॉ एम डी तिवारी की स्मृति में स्वर्ण पदक देगा मुक्त विश्वविद्यालय

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने प्रख्यात शिक्षाविद् तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रिपलआईटी, प्रयागराज के पूर्व निदेशक डॉ एम डी तिवारी की स्मृति में दानदाता स्वर्ण पदक देने का निर्णय लिया है। डॉ तिवारी ने ट्रिपल आईटी प्रयागराज की अवधारणात्मक, योजनाबद्ध और विकसित संरचना निर्मित की और स्थापना से 15 वर्षों तक निदेशक के रूप में कार्य किया। वें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे। रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति रहते हुए डॉ तिवारी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए मानक स्थापित किये। मुक्त विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा डॉ तिवारी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। डॉ तिवारी की धर्मपत्नी एवं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की पूर्व उपाचार्य डॉ इति तिवारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने डॉ एम डी तिवारी की स्मृति में दानदाता स्वर्ण पदक दिए जाने का निर्णय लिया। पहली बार प्रारंभ हुए डॉ मुरलीधर तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक को कल 20 वें दीक्षांत समारोह में विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक उमा यादव को प्रदान किया जाएगा। जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि इसके साथ ही 20 वें दीक्षांत समारोह में एक अन्य दानदाता स्वर्ण पदक मुक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी इंदू भूषण पांडेय की पत्नी स्वर्गीय चारुल पांडेय की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। स्वर्गीय चारुल पांडेय स्मृति स्वर्ण पदक स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी नेहा कनौजिया को प्रदान किया जाएगा। स्व.चारुल पांडेय सरकारी सेवा में रहते हुए भी हमेशा सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि लेती थीं।

संतान की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर जीवित्पुत्रिका व्रत महिलाओं ने अपनी संतानों के लिए रखा। संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता जीमूतवाहन व अपने आराध्य का विधिविधान से पूजन-अर्चन किया। त्रिवेणी बांध के आसपास पुरोहितों से व्रत कथा सुनी गई तो जीमूतवाहन का विधिविधान से पूजन करने के बाद पुरोहितों को दान-दक्षिणा की गई। व्रत का पारण सोमवार को किया जाएगा। निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने अपनी संतानों के सुखद जीवन के कामना करते हुए सोने व चांदी से निर्मित जितिया धागा धारण किया। मान्यता के अनुसार व्रत को करने से माताओं के पुत्र पर आए संकट को टालने के लिए स्नान व दान-दक्षिणा की गई। पूजन में फूल-माला, मिठाई व कई प्रकार के फल रखे गए। पूजन के दौरान बांध पर व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। शाम को घर आने पर धागा पुत्रों के गले में बांधा गया।

शिक्षिका रेनू मिश्रा हिन्दी दिवस पर हुईं सम्मानित

हिन्दी दिवस पर दिल्ली में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में दिया गया प्रशस्ति पत्र

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। खेलगांव पब्लिक स्कूल, प्रयागराज की शिक्षिका और सुप्रसिद्ध कवियत्री, साहित्यकार रेनू मिश्रा 'दीपशिखा' को नई दिल्ली में हिन्दी दिवस पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। हिन्दी अकादमी दिल्ली सरकार एवं मधुबन एजुकेशनल बुक्स की ओर से भाषा उत्सव 'हिंदी हैं हम' कार्यक्रम का आयोजन सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया ब्लॉक ए हौज खास, नई दिल्ली में हुआ। ख्यातिलब्ध कवियत्री और साहित्यकार रेनू मिश्रा दीपशिखा को साहित्य के क्षेत्र में पूर्व में भी कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। रेनू मिश्रा को प्रयागराज ही नहीं आसपास के जनपदों और राज्यों में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। जहां वह कई बड़े मंचों पर काव्य पाठ कर तालियां बटोर चुकी हैं। इस मौके पर अतिथियों द्वारा लोगों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कला एवं संस्कृति मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा, विशिष्ट

अतिथि आईएएस डॉ रश्मि सिंह, भाषा विशेषज्ञ प्रो चांद किरण सलूजा, भाषाविद डॉ सुरेश पंत, राजदूत सूरीनाम अरुण कोएमर हार्डियन, वाणिज्यिक सलाहकार ईरान दूतावास डॉ होसैन बामिरी, अखिल विश्व हिंदी समिति, टोरंटो ओंटारियो, कनाडा के अध्यक्ष गोपाल बघेल, कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ एवं पूर्व सलाहकार गृहमंत्री भारत सरकार ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, समाचार वाचक सईद अंसारी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष डॉ प्रवीन गुप्ता, राजभाषा संस्कृति मंत्रालय के सहायक निदेशक राजेश गुप्ता, सांस्कृतिक विभाग चीन दूतावास नई दिल्ली के सचिव शु निंग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक नवीन राजलानी, हिमानी मित्तल आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में स्वच्छता रैली का हुआ आयोजन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। इफको घियानगर फूलपुर में स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में 'स्वच्छता में सहकार ' की भावना के साथ जागरूकता हेतु स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (इकाई प्रमुख) संजय कुदेशिया के नेतृत्व में रैली का शुभारंभ हुआ। स्वच्छता रैली बैनर, पोस्टर तथा स्वच्छता जागरूकता के नारों के साथ निकाली गई जो कि स्वच्छता का संदेश दे रही थी। इसके साथ ही इफको घियानगर कालोनी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (इकाई प्रमुख) संजय कुदेशिया ने कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग बिलकुल ना करें क्योंकि यह धरती एवं समुद्र को दूषित कर रहा है तथा इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता विषय पर सभी वर्ग के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक संजय भंडारी, संयुक्त महाप्रबंधक क्रमशः रत्नेश कुमार, एस.के.सिंह, आर.पी.यादव, विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर, अनिल कुमार सिंह, डी.के.शुक्ल, उमेश कुमार, नीरज कुमार तथा बड़ी संख्या में बच्चें, महिलाएं तथा इफको कर्मचारी शामिल रहे।

क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट समिति का 12वाँ वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट समिति द्वारा इस मानसून सत्र का 12वाँ वृक्षारोपण

अभियान जिला कारागार, सुद्धोवाला देहरादून में सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के 100 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया। जिला कारागार में सम्पन्न किया गया ये वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वितीय चरण का अभियान है। लगाए गए वृक्षों में आम, नीम, पिलखन, चंपा, बॉटलब्रश, कनेर, जामुन इत्यादि के वृक्ष शामिल किए गए।

पूरे कार्य का संयोजन व विशेष सहयोग राम कपूर, संस्थापक एवं अध्यक्ष, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी ने किया। संस्था का प्रत्येक सदस्य इस कार्य हेतु तन मन धन से पर्यावरण के संरक्षण हेतु समर्पित रहा। इस मानसून सत्र में अभी तक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट द्वारा 2000 से अधिक वृक्षों का रोपण किया जा चुका है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी अतिथियों ने सोसाइटी के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक हरियाली फैलाने और वृक्ष लगाने का आह्वान किया और साथ ही समिति लगातार द्वारा किए जा वृक्षारोपण अभियानों की खूब सराहना की। इस वृक्षारोपण अभियान में समिति के अध्यक्ष राम कपूर, सचिव जे पी किमोठी, कोषाध्यक्ष शंभू शुक्ला, संयोजक नितिन कुमार, हर्षवर्धन जमलोकी, राजेश बाली, रविन्द्र सिंह खालसा, गगन चावला, दीपक सिंह, दिवाकर नैथानी, एडवोकेट दीपक कुमार, मंजुला रावत, सोनिया, सन्नी कुमार, प्रकाश गोदियाल, ऋषभ रावत, दीपक वासुदेव, शिवम, सुंदर, आर के जोशी तथा जेल प्रशासन से जेलर पवन कोठारी, डिप्टी जेलर विवेक शुक्ला, सब इंस्पेक्टर अरविंद रावत, मौजूद रहे।

भारतेन्द्र त्रिपाठी श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किए गए

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजौना जसरा प्रयागराज के सहायक अध्यापक भारतेन्द्र कुमार त्रिपाठी को बीबीएस इंटर कालेज गोहरी फाफामऊ प्रयागराज में अशासकीय स्ववित्त पोषित विद्यालय महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित डां राधाकृष्णन श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह में में सम्मानित किया गया।शिक्षक विधायक डॉ बाबूलाल तिवारी ने उन्हें माल्यार्पण कर अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को प्रोत्साहित किया।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक आर एन विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पी एन सिंह, भाजपा प्रशिक्षण अभियान उत्तर प्रदेश के सह संयोजक डॉ शैलेश कुमार पाण्डेय सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। शजूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय और महामंत्री राजेंद्र अनुरागी सहित तमाम शिक्षकों ने श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिया।

10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 580 मरीज देखे गए - डॉ. जी. एस. तोमर

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, कतवारूपुर, हनुमानगंज में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हण्डिया के पूर्व प्राचार्य डॉ जी एस तोमर की अगुवाई में डॉ वीएन त्रिपाठी, डॉ सुभाष राय, डॉ रंजना तिवारी, डॉ अवनीश पाण्डेय, डॉ कामता प्रसाद, डॉ आशीष मौर्य एवं डॉ अविनाश सिंह सहित ख्यातिलब्ध चिकित्सकों की टीम ने पाँच सौ अस्सी रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया । इस अवसर पर उपस्थित मरीजों की हड्डियों की मजबूती की जाँच (बोन मिनरल डेंसिटी), ब्लड सुगर एवं हीमोग्लोबिन का परीक्षण भी निःशुल्क किया गया । साथ ही साथ उनको आयुर्वेदीय जीवनशैली एवं खानपान की जानकारी सहित रोज़मर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आसपास उपलब्ध जड़ीबूटियो की जानकारी भी प्रदान की गई ।

इस अवसर पर सुदर्शन आयुर्वेद सेंटर के डायरेक्टर राजेन्द्र सिंह ने शिविर की समुचित व्यवस्था की एवं एवं अखिलेन्द्र सिंह, अंकुर सिंह, मनीष त्रिपाठी, रणविजय सिंह, विवेक गुप्ता, एम के सिंह, उत्तम श्रीवास्तव, नीरज त्रिपाठी, अशोक मिश्रा एवं अनिल यादव आदि ने सहयोग प्रदान किया । जाँच एवं औषधि वितरण में प्रवेक कल्प, एमिल, झंडु, अमृतालय, अक्षय फार्मा, नागार्जुन, स्वास्थ्य वर्धक? वशिष्ठा, साण्डू, आर्ब्रो आदि औषधि निर्माणशालाओं ने निःशुल्क जाँच एवं औषधियों की आपूर्ति की ।

विद्यार्थियों को दी गई स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) चायल के कसेंदा प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और फिल्म एंड थिएटर विभाग के छात्रों ने किया। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से छात्रों ने संतुलित आहार, मोटे अनाज (मिलेट्स) का महत्व, पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाई। विद्यार्थियों को बताया गया कि मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ-साथ अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक होते हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पेंसिल किट, कॉपी, चॉकलेट और बिस्किट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. श्रीवत्सल, डॉ. रश्मि सिंह, डॉ. तिलक आनंद, डॉ. शायरा सुलतान, डॉ. ममता सुगंधा, डॉ. शिल्पा यादव सहित कई शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था कमिश्नरेट प्रयागराज अजय पाल शर्मा द्वारा त्रिवेणी सभागार रिजर्व पुलिस लाइन्स प्रयागराज में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली(के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें पुलिस उपायुक्त यमुनानगर, पुलिस उपायुक्त नगर तथा समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी व आईजीआरएस कर्मचारीगण उपस्थित रहें। सम्बन्धित को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

भिवंडी से नवी मुंबई तक सांसद बाल्या मामा की कार रैली को हजारों नागरिकों का उत्स्फूर्त समर्थन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील के नाम पर किया जाए, इस मांग को लेकर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ़ बाळ्या मामा के नेतृत्व में रविवार को भिवंडी से नवी मुंबई तक भव्य कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को स्थानीय भूमिपुत्रों और नागरिकों ने जोरदार प्रतिसाद दिया और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। मानकोली-डोंबिवली मार्ग पर स्व. दि.बा. पाटील की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करने के बाद यह रैली रवाना हुई। इस अवसर पर ठाणे जिले के वरिष्ठ नेता आर. सी. पाटील, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट) के उपनेता विश्वास थले, मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष डी. के. म्हात्रे, शिवसेना ठाकरे गट के जिल्हा प्रमुख कुंदन पाटील, राकांपा (शरद पवार गट) की महिला जिलाध्यक्ष डॉ. रूपाली कराले, पूर्व जिला परिषद सदस्य शारदा सुरेश म्हात्रे समेत बड़ी संख्या में भिवंडी तालुका के बहुजन समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदित हो कि ठाणे, रायगड, पालघर, मुंबई और नवी मुंबई के भूमिपुत्र आगरी-कोली समाज की यह लंबे समय से मांग रही है कि नवी मुंबई हवाई अड्डे को दि.बा. पाटील का नाम दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र की ओर से अब तक निर्णय न आने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सांसद बाल्या मामा ने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने और नामकरण की मांग को बुलंद करने के लिए इस कार रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर टालमटोल की, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह को होने नहीं दिया जाएगा। इस आंदोलन को वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी समर्थन दिया। भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रदीप शिर्के ने सांसद को लिखित समर्थन पत्र सौंपा। रैली के दौरान विभिन्न संस्थाओं और संगठनों ने भी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। खास बात यह रही कि मानकोली, खारेगांव, कलवा, विटावा समेत कई जगहों पर स्थानीय नागरिकों ने पारंपरिक पोशाकों में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत कोली नृत्य और जल्लोषी स्वागत से रैली का भव्य स्वागत किया।

भिवंडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विवादों में, अधिकारी हथियार लेकर पहुँचे बाजार-वीडियो वायरल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में फुटपाथों पर फैले अतिक्रमण से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो चुका है। जगह-जगह हाथगाड़ियां और लावारिस वाहन यातायात को बाधित कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पालिका प्रशासन ने 9 सितंबर 2025 को अतिक्रमण निष्कासन पथक गठित किया, जिसकी जिम्मेदारी अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण विभाग के प्रभारी प्रमुख अरविन्द गोविन्द घुंगरे को सौंपी गई। इस टीम में पांच अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। शनिवार को यह पथक पद्मानगर स्थित सब्जी बाजार में कार्रवाई के लिए पहुँचा। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान विभाग प्रमुख अरविन्द घुंगरे ने सब्जी विक्रेताओं को धारदार हथियार दिखाकर धमकाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोग दुकानें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नगरसेवक संतोष शेट्टी मौके पर पहुँचे और उन्होंने तुरंत पालिका आयुक्त अनमोल सागर को फोन कर अधिकारी की शिकायत दर्ज कराई

शहरवासियों का कहना है कि पालिका की कार्रवाई अक्सर चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहती है। मुख्य बाजार क्षेत्र तीन बत्ती परिसर में कथित रूप से रिश्वत लेकर हाथगाड़ियां लगाई जाती हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अतिक्रमण विभाग प्रमुख का पद तकनीकी योग्यता वाले बिल्डिंग कम इंस्पेक्टर के लिए निर्धारित है, लेकिन भिवंडी पालिका में यह जिम्मेदारी डिग्रीधारकों के बजाय अन्य कर्मचारियों को देने की परम्परा प्रशासक काल में चलता आ रहा है।नतीजतन आए दिन विवाद और अपवाद खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं।

ठाणे जिले में वोट चोरी विरोधी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी कांग्रेस -दयानंद चोरघे

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता पाने के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इसके खिलाफ राज्य भर में बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में ठाणे ग्रामीण जिला कांग्रेस समिति ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक 'वोट चोरी विरोधी हस्ताक्षर अभियान' चलाने का निर्णय लिया है। ठाणे ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद चोरघे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मतदार अधिकार यात्रा' के बाद अब दूसरे चरण में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत ठाणे ग्रामीण जिले के सभी ब्लॉकों और बूथ स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनसे हस्ताक्षर लिए जाएंगे।दयानंद चोरघे ने कहा कि जिला, तालुका और ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारियों को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। हर ब्लॉक अध्यक्ष, आघाडी, विभाग और सेल प्रमुखों को बूथ और मंडल स्तर पर जाकर लोगों को वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करना होगा।उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच कर इस अभियान को सफल बनाया जाए। साथ ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों से भी आह्वान किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस हस्ताक्षर अभियान में बड़े पैमाने पर शामिल हों।

भिवंडी का पानी माफिया नालों से कर रहा सप्लाई, जलापूर्ति विभाग बना मौन दर्शक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपूर शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। नागरिकों को रात 2 से 3 बजे नलों में पानी नसीब होता है, लेकिन टंकियों तक पानी पहुंचने से पहले ही माफियाओं की मोटी पाइपलाइनें उसे हजम कर लेती हैं। हालात यह हैं कि शहर के काई टंकी को ध्वस्त कर दिया गया और बची टंकियां की देखरेख मरम्मत ना होने से जर्जर हो चुकी है। कामतघर हनुमान मंदिर के पास की टंकी जर्जर हालत में है। उसमें पानी भरते ही दिनभर बरसात जैसी धार टपकती रहती है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। जिसका सबूत है। इस बीच, नारपोली नाले में दर्जनभर अवैध पाइपलाइनें डालकर सीधे डाइंग-साइजिंग कंपनियों तक पानी सप्लाई किया जा रहा है। शहर में ऐसी करीब 150-200 कंपनियां हैं, जिन्हें कपड़ा रंगाई और प्रोसेसिंग के लिए लाखों लीटर पानी चाहिए। स्थानीय आरोप है कि पानी माफिया इन कंपनियों को प्रचुर मात्रा में पानी सप्लाई कर रहे हैं और इसके बदले मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व आयुक्त द्वारा गठित भरारी पथक और जलापूर्ति अभियंता इस अवैध धंधे से अनजान नहीं हैं। छोटे पानी चोरों पर कागजी कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन बड़े माफियाओं पर कभी शिकंजा नहीं कसां नहीं जाता। नागरिकों का आरोप है कि माफिया, रसूखदार नेताओं और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से ही यह करोड़ों का कारोबार फल-फूल रहा है। दक्ष नागरिकों की माने तो जब जनता बूंद-बूंद के लिए तरस रही है, तब नालों से बहती यह अवैध सप्लाई किसकी जेब भर रही है ? जलापूर्ति विभाग की चुप्पी अब उसकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी को पालिका आयुक्त का नोटिस

सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नही-आयुक्त अनमोल सागर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र के टेमघर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में 8 सितम्बर की मध्यरात्रि क्लोरीन गैस का रिसाव होते ही हड़कंप मच गया। रात करीब 12:40 बजे घटी इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। क्लोरीन गैस का अत्यधिक संपर्क जानलेवा साबित हो सकता था,लेकिन आयुक्त अनमोल सागर की त्वरित कार्रवाई और प्रशासन की तत्परता से शहर एक बड़ी त्रासदी से बच गया। जैसे ही रिसाव की सूचना पालिका प्रशासन को मिली, तुरंत अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके, पानी पुरवठा अभियंता संदीप पटनावर, आपत्ती व्यवस्थापक साकिब खर्बे और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने विशेष उपकरण और पीपीई किट की मदद से रिसाव पर नियंत्रण पाया। हालांकि इस बीच पांच कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए जिन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त अनमोल सागर खुद हालात की निगरानी में जुट गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि रिसाव थोड़ी देर और जारी रहता तो आसपास के सैकड़ों लोग जानलेवा खतरे में आ सकते थे। लेकिन प्रशासन की सतर्कता और आयुक्त सागर के मजबूत नेतृत्व ने हालात को काबू में कर लिया। घटना के बाद आयुक्त ने स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी करते हुए चेताया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कंपनी को जवाबदेही तय करने, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और उपकरणों की नियमित जांच के सख्त आदेश दिए। नागरिकों ने भी आयुक्त की दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कारण ही भिवंडी एक भीषण हादसे से बच सका। इस घटना ने साबित कर दिया कि सजग प्रशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नेतृत्व हर संकट को मात दे सकता है।

'हमारा सिंदूर -हमारा देश, पाकिस्तान से कोई खेल नहीं'

पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के फैसले के खिलाफ भिवंडी में शिवसेना का जोरदार विरोध

महिलाओं ने सिंदूर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री मोदी को भेजा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भिवंडी में शिवसेना पदाधिकारियों और महिला आघाडी की ओर से रविवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेले जा रहे क्रिकेट मैच का तीव्र विरोध करते हुए इसे 'शहीदों और भारतीय नारी के सिंदूर का अपमान' बताया। यह आंदोलन छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पर जिल्हा प्रमुख मनोज गगे और लोकसभा महिला संपर्क संघटिका आशा रसाल के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस मौके पर उपनेता विश्वास थले, जिल्हा संघटिका वैशाली मेस्त्री, जिल्हा सचिव राजाभाऊ पुण्यार्थी, महिला तालुका संघटिका फशी पाटील, तालुका संपर्क प्रमुख कृष्णा वाकडे, माजी शहर प्रमुख मोहन दादा वल्लाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महिला कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदुस्तानी नागरिकों की जान ली, तब भी भारत सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है, जो शहीदों और देश का अपमान है। आंदोलन के दौरान महिला पदाधिकारियों ने अपने-अपने सिंदूर इकट्ठा कर एक डिब्बे में रखा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। इस प्रतीकात्मक कदम के जरिए उन्होंने संदेश दिया कि 'हमारा सिंदूर, हमारा देश' और इसके अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस अवसर पर नितेश दांडेकर, व्यापारी संघटना अध्यक्ष मनीष बंटी गिरी, संतोष हकारे, भाई वनगे, संतोष भावारथे, विजय कुंभार, विजय भोईर, अमोल अहीरे, सचिन कोंडलेकर, मोहम्मद मोमीन, दिपाली जैन, अरुणा पाटील, संगीता जोशी, सुनिता तरे, मिरा भानुशाली, नरेश शिवदे, गणेश घोसके, नितीन काठवले, शरद पांडव, नौशबा अन्सारी, कल्पना पुजारी, राजू पातकर, स्वाती भावार्थी, योगिता अहिरे, सारिका रेवाले, विद्या गुलवी, अनुष्का गुप्ता, भावना दमरे, छाया माली, मालती पाटील और सायली पाटील समेत बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी और महिला आघाडी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रहस्यमय मौत, मां ने लगाया जहर देने का आरोप; प्रेमी गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा आनंदिता सोरेन की रहस्यमय मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। छात्रा की मौत के बाद उसके प्रेमी और मालदा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर उज्ज्वल सोरेन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। परिवार ने लड़की की मौत के पीछे उसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

छात्रा की मां अल्पना टुडू ने इंग्लिशबाजार थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि उनकी बेटी को उसके प्रेमी ने जहर देकर मारा है। उनका दावा है कि आनंदिता अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से पंजीकृत शादी में बदलना चाहती थी, लेकिन उज्ज्वल इससे बच रहा था। इसी तनाव के चलते दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे।

पुरी मंदिर में दोनों ने की थी शादी

शिकायत में यह भी बताया गया कि आनंदिता और उज्ज्वल हाल ही में पुरी गए थे, जहां एक मंदिर में गुप्त रूप से शादी की थी। लेकिन लौटने के बाद उज्ज्वल ने शादी का पंजीकरण कराने से साफ इनकार कर दिया। मां के अनुसार, यही बात उनकी बेटी की परेशानी और मानसिक दबाव की वजह बनी।

हॉस्पिटल में दिखे संदिग्ध लक्षण

परिवार का कहना है कि जब उन्होंने आनंदिता को अस्पताल के सीसीयू में देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मां ने कहा कि हमें कल रात फोन आया कि बेटी की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल लाया गया है। आज हमें उसकी मौत की खबर मिली। हम चाहते हैं कि पुलिस पूरी तरह से जांच करे।

सोशल मीडिया से शुरू हुई थी दोस्ती

आनंदिता दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट की रहने वाली थीं। उनकी मुलाकात उज्ज्वल से सोशल मीडिया और मेडिकल कार्यक्रमों में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया। लेकिन मां के मुताबिक, रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ रहा था।

भारतीय कुश्ती को बड़ा झटका अमन सहरावत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आयोग्य घोषित

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ज्यादा वजन होने के कारण जगरेब में चल रही प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बता दें कि, पिछले साल अमन ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2023 में जारी यूडब्ल्यूडब्ल्यू नियमों के अनुसार, विश्व कप, यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए दो किग्रा तक ज्यादा वजन तक की मंजूरी है। हालांकि, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे टूर्नामेंटों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

बता दें कि, पेरिस ओलंपिक2024 में विनेश फोगाट को उनके गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग में ज्यादा वजन होने के कारण प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब विनेश फोगाट का वजन 50 किग्रा से कुछ ग्राम ज्यादा था। इस दिल तोड़ने वाली खबर से पूरा देश स्तब्ध था। वहीं भारतीय दल के एक सूत्र ने जगरेब से पीटीआई को बताया कि, ये दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्चजनक है कि अमन अपना वजन नियंत्रित नहीं रख सका। जब वह वजन मापने के लिए खड़ा हुआ तो उसका वजन 1700 ग्राम ज्यादा था। ये स्वीकार्य नहीं है। उसका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया ये हमारी समझ से परे है।

'सोचा जरूर पर हुआ नहीं, शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता', शमी ने आत्महत्या के विचारों को किया याद

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने स्वीकार किया कि उनके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है।

रजत शर्मा के साथ आप की अदालत के एपिसोड में अपने विचार प्रकट करते हुए भारतीय स्टार तेज गेंदबाज ने कहा, 'सोचा जरूर पर हुआ नहीं, ये शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता मेरे से क्योंकि जब सोचा था कि मेरे दिमाग में ये समय है जिंदगी के अंत का, जिस चीज के लिए मुझे इतना नाम दिया, जिस चीज के लिए मीडिया मेरे पीछे है, उसको छोड़ के इस जंप के चक्कर में...वो सोचा, वो प्यार याद आया। सोचा चलो इसको छोड़ा, चलो गेम में लगते हैं फिर...' इस साल जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को भरण-पोषण के रूप में 4 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। जहां को 1.50 लाख रुपए प्रति माह देने होंगे जबकि बेटी को 2.50 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। पूर्व मॉडल हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी। इस जोड़े को 2015 में एक बेटी हुई। मोहम्मद शमी और हसीन जहां 2018 में अलग हो गए थे जब उन्होंने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था।

घरेलू हिंसा के आरोप के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में कही गई अपमानजनक बातों के बारे में पूछे जाने पर शमी ने जवाब दिया, 'बुरी बातें कही जाती हैं, लेकिन आजकल उन बातों के बारे में भी बात की जाती है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है... मुझे सबसे ज़्यादा इसी से डर लगता है। कल मैं एक तस्वीर देख रही था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने उसे कब खींच लिया था।

पिछले 6-7 सालों में मुझ पर जितने आरोप लगे हैं, शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप न लगे हों। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।' हसीन जहां ने 2018 में क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उन्होंने अलीपुर कोर्ट में एक याचिका दायर कर शमी और उनके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जहां ने परिवार के भरण-पोषण के लिए तेज गेंदबाज से 7 लाख रुपए प्रति माह की मांग की थी। शमी ने आखिरी बार 2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (घ्ङ्थ) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक प्रतिस्पर्धी मैच खेला था। वह मैच इस तेज गेंदबाज के लिए यादगार नहीं रहा था, क्योंकि गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था और उन्होंने तीन ओवरों में 48 रन दिए थे।

चैंपियंस ट्रॉफी अभियान में शमी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे थे। वह भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, उन्होंने 5 मैचों में 9 विकेट लिए, उनके साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी थे जिन्होंने सिर्फ तीन मैचों में इतने ही विकेट लिए। शमी के प्रयासों की बदौलत भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट क्रिकेट 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में खेला था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जाता है या नहीं।

अडानी पावर बिहार में बिजली परियोजना के लिए तीन अरब डॉलर का निवेश करेगी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अडानी पावर बिहार में तीन अरब डॉलर (करीब 26, 482 करोड़ रुपए) के निवेश से 2, 400 मेगावाट का अत्याधुनिक बिजली संयंत्र स्थापित करेगी। अडानी समूह की कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के साथ 25 साल के विद्युत आपूर्ति समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य के भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाली परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह पीपीए, अगस्त में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) की ओर से बीएसपीजीसीएल द्वारा अडानी पावर को जारी किए गए स्वीकृति पत्र के अतिरिक्त है।

अडानी पावर ने 6.075 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम आपूर्ति दर की पेशकश करके यह परियोजना हासिल की। कंपनी ने कहा कि वह नए संयंत्र और उससे संबंधित अवसंरचना के निर्माण के लिए लगभग तीन अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। यह परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य है कि संयंत्र को 60 महीनों के भीतर चालू कर दिया जाए। विद्युत संयंत्र के लिए कोयला लिंकेज भारत सरकार की शक्ति नीति के अंतर्गत आवंटित किया गया है। इस परियोजना से निर्माण चरण के दौरान 10, 000-12, 000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा तथा परिचालन शुरू होने पर 3, 000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा।

जीएसटी सुधारों का लाभ दिन की शुरुआत से रात को सोने जाने तक सभी उत्पादों पर मिलेगा : सीतारमण

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक बड़ी जीत है। सीतारमण ने रविवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य के अपने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दीपावली से पहले जीएसटी सुधारों को लागू करने के निर्देश से बहुत पहले ही इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया है। चेन्नई सिटीजन्स फोरम द्वारा आयोजित 'उभरते भारत के लिए कर सुधार' कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि माल एवं सेवा कर का लाभकारी प्रभाव सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सभी उत्पादों पर रहेगा। कुछ प्रमुख पहल का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले जीएसटी के तहत 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उनपर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लगेगा। नए जीएसटी सुधार (2.0) 22 सितंबर से लागू होंगे।

कार्तिकियन के चार और और सारांश के तीन विकेट सेंट्रल जोन का दलीप ट्रॉफी चैंपियन बनना तय

बेंगलुरु **(एजेंसी)**। कुमार कार्तिकियन (चार विकेट) और सारांश जैन (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत सेंट्रल जोन ने रविवार को दलीप ट्रॉफी मुकाबले के चौथे दिन साउथ जोन को 426 के स्कोर पर समेट दिया। सेंट्रल जोन को अब जीत के लिए 65 रन बनाने है तथा अभी एक दिन का खेल शेष है। साउथ जोन ने कल के दो विकेट पर 192 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज साउथ जोन ने कल के स्कोर में महज 30 रन जोड़कर अपने चार विकेट गंवा दिए। साउथ जोन का तीसरा विकेट रिकी भुई (45) के रूप में गिरा। उन्हें दीपक चाहर ने एस शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (27) को कुमार कार्तिकेय ने अपना शिकार बना लिया। सलमान निजार (12) और आर स्मरण (47) भी कार्तिकेयन का शिकार बने।

222 के स्कोर पर छह विकेट गंवा चुकी हार की डगर पर खड़ी साउथ जोन को अंकित शर्मा और सी आंद्रे सिद्धार्थ की जोड़ी ने संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 330 गेंदों में 192 रनों की साझेदारी हुई। कार्तिकेयन ने शतक की ओर बढ़ रहे अंकित शर्मा को आर पाटीदार के साथ हाथों कैच आउट कराकर सेंट्रल जोन को बड़ी सफलता दिलाई। अंकित शर्मा ने 168 गेंदों में 13 चौके और एक छक्के की मदद से 99 रन बनाए। वह महज एक रन से शतक से चूक गए।

गुरजपनीत सिंह (नाबाद तीन) को सारांश जैन ने आउट किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 426 के स्कोर पर समेट दिया। हालांकि उसे 64 रनों की बढ़त हासिल हुई। सेंट्रल जोन को जीत के लिए 65 रन बनाने हैं और अभी एक दिन का खेल शेष है। ऐसे में सेट्रल जोन का चैंपियन बनना तय है। सी आंद्रे सिद्धार्थ 84 रन बनाकर नाबाद रहे। सेंट्रल जोन की ओर से कुमार कार्तिकियन ने चार विकेट लिए। सारांश जैन को तीन विकेट मिले। कुलदीप सेन और दीपक चाहर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

फ्लिपकार्ट इंडिया का घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5, 189 करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एकीकृत घाटा वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में बढ़कर 5, 189 करोड़ रुपये हो गया।

कारोबार खूफिया मंच टॉफलर द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी के लिए फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। इससे पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में फ्लिपकार्ट इंडिया का घाटा 4, 248.3 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन से एकीकृत आय में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 70, 541.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 82, 787.3 करोड़ रुपये हो गई।

टॉफलर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी का कुल व्यय 17.4 प्रतिशत बढ़कर 88, 121.4 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की वित्तीय लागत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 57 प्रतिशत बढ़कर लगभग 454 करोड़ रुपये हो गई।

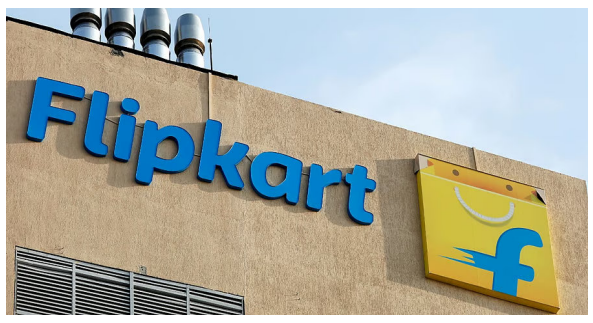

भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, एशिया कप 2025 मुकाबले से पहले कोहली के बचपन के कोच

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत रविवार को दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है। के कोच राजकुमार शर्मा ने टीम इंडिया के विजयी होने का वादा किया है। शर्मा ने कहा, 'भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है कि भारतीय टीम यह मैच जीतेगी। भारतीय टीम बहुत संतुलित है और मैं टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।' दोनों टीमें अपने-अपने शुरुआती मैचों में शानदार जीत के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं। भारत ने अपने पहले मैच में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात पर 9 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से आसानी से हराया था।

यह नतीजा रविवार के मुकाबले को सुपर 4 की दौड़ में अहम बनाता है। यहां जीत न केवल गर्व का विषय बनती है, बल्कि शुरुआती क्वालीफिकेशन की संभावनाओं को भी मजबूत करती है। वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 पुरुष टी20आई क्रिकेट टीम भारत मौजूदा विश्व और महाद्वीपीय चैंपियन है। वे आठ खिताबों के साथ एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल टीम भी हैं। सूर्यकुमार यादव संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे। इस टीम में फॉर्म में चल रहे युवा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, इंडियन प्रीमियर लीग के स्टार रिंकू सिंह और जितेश शर्मा, और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली एक मजबूत गेंदबाजी इकाई भी शामिल है। टी20आई रैंकिंग में सातवें स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले भी दो बार एशिया कप जीत चुकी है और सलमान अली आगा की कप्तानी में तीसरा खिताब जीतने की कोशिश में है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा गया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में अभी भी फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों के साथ हर क्षेत्र में काफी दमखम है। भारत बनाम पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता टी20आई प्रारूप में 13 बार खेली गई है जिसमें भारत 9-3 से आगे है। पाकिस्तान की तीन जीत में से एक दुबई में 2022 एशिया कप में आई थी। भारत ने 2024 टी20 विश्व कप में पिछली बार जब दोनों टीमें मिली थीं तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को 6 रनों से हराया था। बुमराह ने एक जादुई स्पेल डालकर मैच का रुख पलट दिया था, जब पाकिस्तान जीत का स्पष्ट दावेदार लग रहा था। एशिया कप के मंच पर भारत और पाकिस्तान एकदिवसीय और टी20द्ददोनों प्रारूपों में 19 बार भिड़ चुके हैं। भारत ने 10 जीते हैं, पाकिस्तान ने छह और तीन मैच रद्द हो गए थे।

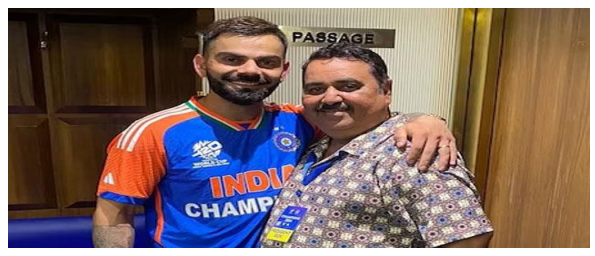

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 9 लाख लगाएं और पाएं 13 लाख

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अगर आपके पास कोई एकमुश्त रकम है और आप उसे किसी सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह सरकार समर्थित छोटी बचत योजना है जिस पर सरकार हर तीन महीने में ब्याज दर तय करती है।

एनएससी में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप इसमें सिंगल या जॉइंट अकाउंट (अधिकतम 3 वयस्क) खोल सकते हैं। नाबालिग के लिए अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। इस स्कीम में आप कम से कम ?1, 000 का निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एनएससी में निवेश की गई रकम पर धारा 80ण के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर आप इस सर्टिफिकेट को बैंकों में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस ऌण पर 7.7इ की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर मिल रही है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। अगर आप इस स्कीम में एकमुश्त ?9, 00, 000 का निवेश करते हैं तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको ?13, 04, 130 मिलेंगे। इस तरह आपकी कुल ब्याज आय ?4, 04, 130 होगी।

'देवों के देव महादेव' की एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया के घर जल्द गूंजेगी किलकारियां

अभिनेत्री समुद्र किनारे क्यूट बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती नजर आई

'देवों के देव महादेव' शो में पार्वती किरदार से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया और उनके पति विकास पाराशर ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के बीच गुड न्यूज शेयर की है। जल्द ही कपल के घर में गूंजेगी किलकारियां। एक्ट्रेस भी मातृत्व के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी साझा की। अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करते हुए सोनारिका ने कैप्शन में लिखा, 'हमारा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर।' तस्वीरों में एक्ट्रेस अपना क्यूट बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस अपनी प्रग्नेंसी की दूसरी तिमाही में हैं। तस्वीरों में सोनारिका वाइट लेस वाली आउटफिट पहने अपने पति के साथ समुद्र किनारे खूबसूरत दृश्य के सामने पोज़ देती नजर आ रही हैं।

सोनारिका और विकास अपनी खुशखबरी का इज़हार करते हुए हाथों में हाथ डाले और रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनारिका भदौरिया ने फरवरी 2024 में बिजनेसमैन विकास पाराशर से शादी की थी। यह बच्चा इस कपल का पहला बच्चा होगा। विकास और सोनारिका लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। इस कपल ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी शादी का फैसला किया था। वहीं शादी के बाद सोनारिका ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लिया और टीवी प्रोजेक्ट्स भी दूर रहीं। सोनारिका ने साल 2011 में 'तुम देना साथ मेरा' शो से टेलीविजन पर शुरुआत की थी। लेकिन 'देवों के देव... महादेव' शो में देवी पार्वती के किरदार ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई और उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। एक्ट्रेस के चेहरे की मासूमियत और सॉफ्ट हार्ट ने दर्शकों को देवी पार्वती के किरदार में तुरंत अपना दीवाना बना दिया। एक्ट्रेस को जादूगाडु और ईदो रकम आदो रकम जैसी तेलुगु फिल्मों में भी देखा गया था। फिल्मों में काम करने के बाद अभिनेत्री ने पृथ्वी वल्लभ, दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली और इश्क में मरजावां से टेलीविजन शो पर वापसी की।

पवन सिंह विवाद के बाद एक्ट्रेस अंजलि राघव ने की अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात, कथावाचक से पूछा सवाल

हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह अभिनेत्री की कमर को स्टेज पर सभी लोगों के सामने टच करते हुए नजर आए थे। जैसे ही उनका यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंजलि ने लाइव आकर पावर स्टार पर कई आरोप लगाए।

हालांकि, बाद में वह मुद्दा सुलझ गया था, क्योंकि पवन सिंह ने भी अंजलि राघव से माफी मांग ली थी, लेकिन इस विवाद के बीच अब अभिनेत्री का एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम जाकर उनसे मुलाकात की और सवाल भी किया। इस पर अनिरुद्धाचार्य ने जो जवाब दिया वह अब काफी वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर अंजलि राघव और अनिरुद्धाचार्य की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसमें एक्ट्रेस ने कहा, 'काफी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं, जो विरोध में होते हैं। मीम्स बनवाते हैं, अलग-अलग कुछ लिखकर डाल देते हैं। ऐसे में मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए।'

इसके बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जवाब देते हुए कहा, 'एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से जब चलता है न तो कुत्ते भोंकते ही हैं, इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना। कुत्तों को जवाब देने की जरुरत नहीं है।' अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद अंजलि राघव ने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन बाद में जब भोजपुरी स्टार ने माफी मांगी, तो एक्ट्रेस ने उन्हें माफ कर दिया। इस मामले में आम्रपाली दुबे ने भी रिएक्ट किया था। उन्होंने पवन सिंह और अंजलि राघव के वीडियो पर क्या कहा, उसे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

चिराग का साथ रहा तो अमरपुर में बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं जयंत राज कुशवाहा

पटना **(एजेंसी)**। अमरपुर विधानसभा सीट बांका जिले में स्थित है...अमरपुर विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेसी कैंडिडेट पशुपति सिंह चुनाव जीते थे। 1957 और 1962 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और शीतल प्रसाद भगत चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1967 में एस.एन. सिंह और 1969 में सुख नारायण सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। साल 1972 में भारतीय जन संघ के कैंडिडेट जनार्दन यादव विधायक बने थे।

इसके बाद 1977 में भी जनार्दन यादव ही अमरपुर से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वे जनता पार्टी के तरफ से चुनावी मैदान में थे। इसके बाद 1980 और 1985 में कांग्रेस कैंडिडेट नील मोहन सिंह विधायक चुने गए थे।

1990 में इस सीट पर निर्दलीय माधो मंडल चुनाव जीते थे। 1995 से 2005 तक इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा और सुरेंद्र प्रसाद सिंह लगातार तीन बार अमरपुर से विधायक चुने गए थे। 2010 और 2015 में जेडीयू कैंडिडेट जनार्दन मांझी लगातार दो बार विधायक चुने गए। 2020 में यहां से जेडीयू कैंडिडेट जयंत राज ने जीत हासिल की थी। जयंत राज प्रभावशाली कोइरी लीडर हैं। साथ ही में वे बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए अमरपुर में उनकी दावेदारी इस बार भी पक्की लग रही है।

वहीं 2020 के चुनाव में अमरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट जयंत राज ने जीत हासिल की थी। जयंत राज को 54 हजार तीन सौ आठ वोट मिला था तो कांग्रेस कैंडिडेट जितेंद्र सिंह 51 हजार एक सौ 94 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से जयंत राज ने जितेंद्र सिंह को महज तीन हजार एक सौ 14 वोट के कम अंतर से हरा दिया। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मृणाल शेखर 40 हजार तीन सौ आठ वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अमरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट जनार्दन मांझी ने जीत हासिल की थी। जनार्दन मांझी ने बीजेपी कैंडिडेट मृणाल शेखर को 11 हजार सात सौ 69 वोटों से हराया था। जनार्दन मांझी को कुल 73 हजार सात सौ सात वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मृणाल शेखर को कुल 61 हजार नौ सौ 34 वोट मिले थे तो वहीं 6 हजार आठ सौ 18 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे।

10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 580 मरीज देखे गए - डॉ जी एस तोमर

प्रयागराज। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, कतवारूपुर, हनुमानगंज में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हण्डिया के पूर्व प्राचार्य डॉ जी एस तोमर की अगुवाई में डॉ वीएन त्रिपाठी, डॉ सुभाष राय, डॉ रंजना तिवारी, डॉ अवनीश पाण्डेय, डॉ कामता प्रसाद, डॉ आशीष मौर्य एवं डॉ अविनाश सिंह सहित ख्यातिलब्ध चिकित्सकों की टीम ने पाँच सौ अस्सी रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया । इस अवसर पर उपस्थित मरीजों की हड्डियों की मजबूती की जाँच (बोन मिनरल डेंसिटी), ब्लड सुगर एवं हीमोग्लोबिन का परीक्षण भी निःशुल्क किया गया । साथ ही साथ उनको आयुर्वेदीय जीवनशैली एवं खानपान की जानकारी सहित रोज़मर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आसपास उपलब्ध जड़ीबूटियो की जानकारी भी प्रदान की गई । इस अवसर पर सुदर्शन आयुर्वेद सेंटर के डायरेक्टर राजेन्द्र सिंह ने शिविर की समुचित व्यवस्था की एवं एवं अखिलेन्द्र सिंह, अंकुर सिंह, मनीष त्रिपाठी, रणविजय सिंह, विवेक गुप्ता, एम के सिंह, उत्तम श्रीवास्तव, नीरज त्रिपाठी , अशोक मिश्रा एवं अनिल यादव आदि ने सहयोग प्रदान किया । जाँच एवं औषधि वितरण में प्रवेक कल्प, एमिल, झंडु, अमृतालय , अक्षय फार्मा, नागार्जुन, स्वास्थ्य वर्धक? वशिष्ठा, साण्डू, आर्ब्रो आदि औषधि निर्माणशालाओं ने निःशुल्क जाँच एवं औषधियों की आपूर्ति की ।

पूर्वोत्तर में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता, असम के उदलगुरी में था भूकंप का केंद्र

कोलकाता। रविवार शाम पूर्वोत्तर और उससे सटे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद डेढ़ घंटे के भीतर तीन और झटके आए, जिससे असम में कम से कम दो लोग घायल हो गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। 5.8 तीव्रता का पहला झटका शाम 4.41 बजे, 3.1 तीव्रता का दूसरा झटका शाम 4.58 बजे और उसके बाद 2.9 तीव्रता का एक और झटका शाम 5.21 बजे महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि चौथा झटका 2.7 तीव्रता का था और शाम 6.11 बजे दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि तीसरे भूकंप का केंद्र असम का सोनितपुर था, जबकि बाकी तीन भूकंप पड़ोसी उदलगुरी जिले में आए।

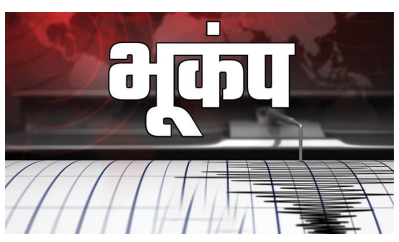

छात्रावास की छत गिरी

असम राज्य आपदा प्रबंधन (एएसडीएमए) ने कहा कि उदलगुरी में एक छात्रावास की छत गिरने से दो लड़कियां घायल हो गईं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। जिले के अमगुरी इलाके में एक घर की छत गिर गई। सोनितपुर में दो घर और एक दुकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि विश्वनाथ जिले में कुछ घरों की दीवारों में हल्की दरारें आ गईं। दरांग और नलबाड़ी जिलों में भी कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया होजई जिले में एक इमारत में दरारें आ गईं।

प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की पूर्वोत्तर यात्रा के बाद कोलकाता पहुंचे थे, ने मुख्यमंत्री सरमा से हालात की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और आपदा प्रबंधन दल नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं। असम सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में झटके भूकंप का असर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी देखा गया। ईटानगर में लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलु ने बताया कि अब तक कोई बड़ी क्षति या हताहत की खबर नहीं मिली है। मणिपुर के पश्चिमी हिस्सों में भी हल्के झटके दर्ज किए गए।

पश्चिम बंगाल तक महसूस हुए झटके असम से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, खासकर सिलीगुड़ी में भी झटके महसूस किए गए।

महागठबंधन के पास एनडीए की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं, उमेश कुशवाहा का हमला

बोले- सीएम नीतीश की नीति का कोई मुकाबला नहीं

पटना **(एजेंसी)**। बिहार जनता दल यूनाईटेड अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े महागठबंधन के पास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है।

कुशवाहा ने रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े महागठबंधन के पास एनडीए की चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तरीय एनडीए सम्मेलनों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे पांचों घटक दलों के कार्यकर्ताओं का उमड़ता सैलाब इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि आगामी चुनाव में विपक्ष की पूरी तरह से सफाया होना तय है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने

एनडीए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प को साकार करने और भावी पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 2025 में 225 का लक्ष्य प्राप्त कर नरेन्द्र मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी को मजबूती दें। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और विकासोन्मुख नीतियों के माध्यम से बिहार को एक नए स्वरूप में संवारा है।

उमेश सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें गरीबी के बाहर निकालने में कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन यापन में सहूलियत प्रदान कर रही है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता से बूथ स्तर पर सघन अभियान चलाकर नीतीश सरकार की उपलब्धियों को हर मतदाता तक सही और सटीक रूप में पहुंचाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार की नीति का कोई मुकाबला नहीं है और उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है।

इजरायल पर खाड़ी देशों का पलटवार : कतर हमले के बाद सऊदी- यूएई हुए एकजुट, 'इस्लामिक नाटो' बनाने को तैयार!

तेल अवीव **(एजेंसी)**। कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल के हालिया हमले ने पूरे अरब जगत को झकझोर दिया है। इस हमले को लेकर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अब इन देशों में विचार हो रहा है कि वे एकजुट होकर इजरायल को कड़ा जवाब दें । चाहे वह कूटनीतिक, सैन्य या आर्थिक मोर्चे पर क्यों न हो। कई विशेषज्ञ इसे 'इस्लामिक नाटो' जैसे गठबंधन की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। जून 2025 में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। सितंबर में इजरायल ने दोहा में हमास के राजनीतिक ठिकानों पर हमला कर दिया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा-'यह सिर्फ कतर पर नहीं, पूरे अरब पर हमला है। जवाब सामूहिक होगा।' दोहा में होने वाले अरब और इस्लामी शिखर सम्मेलन में इस पर बड़ा फैसला संभव है। सऊदी अरब ने कहा कि यह हमला अस्वीकार्य है। यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद 24 घंटे के भीतर दोहा पहुँचे और तुरंत कूटनीतिक हलचल शुरू कर दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि खाड़ी देश अब ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जिससे 'भविष्य में इजरायली हमलों की संभावना ही खत्म हो जाए।' कुवैत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बदर अल-सैफ ने कहा - 'अगर हम अब एकजुट नहीं हुए तो अगला निशाना अन्य खाड़ी देश होंगे।' यूएई अब्राहम समझौते में अपनी भागीदारी घटा सकता है, जिसके तहत इजरायल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कतर पहले ही इजरायली हमलों की निंदा का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करवा चुका है। कतर यह भी सोच रहा है कि वह अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका से हट जाए।

खाड़ी देशों के बीच पहले से ही पारस्परिक रक्षा संधि है। 1980 के दशक का प्रायद्वीप ढाल बल समझौता अब सक्रिय किया जा सकता है। वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एकीकृत करने की तैयारी पर विचार हो रहा है। अधिकांश खाड़ी देश अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हैं, लेकिन अब वे अपनी रक्षा क्षमता में विविधता लाने की कोशिश कर सकते हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई के पास खरबों डॉलर के संप्रभु धन कोष हैं। इनका इस्तेमाल इजरायल की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरब देश उन कंपनियों का बहिष्कार कर सकते हैं, जिनकी इजरायल की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है। यह संदेश भी दिया जा सकता है कि 'अगर हम असुरक्षित हैं और इसका कारण इजरायल है, तो हमारा पैसा कहीं और जाएगा।'

भारत के बाद अब चीन के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप, नाटो को चेताया तो ड्रैगन का जवाब आया

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो सहयोगियों पर रूस से तेल खरीदने के लिए नए टैरिफ लगाने की धमकी के बाद, चीन ने वाशिंगटन को कड़ा संदेश दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने स्लोवेनिया में कहा कि बीजिंग न तो युद्ध की साजिश रचता है और न ही उसमें हिस्सा लेता है, और यह भी चेतावनी दी कि प्रतिबंध केवल संघर्षों को और जटिल बनाते हैं। ट्रंप ने नाटो सदस्यों को लिखे एक पत्र में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सभी नाटो देश ऐसा करने पर सहमत हों और रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। ट्रंप ने इन खरीदों को 'चौंकाने वाला' बताया और कहा कि नाटो देश ऐसा करके रूस के साथ अपनी सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं।

अमेरिका पहले ही भारत पर रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए भारी शुल्क लगा चुका है। अब ट्रंप का प्रशासन चीन पर भी इसी तरह के दंड लगाने पर जोर दे रहा है, जिसे रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक 'जीवन रेखा' माना जाता है। अमेरिकी अधिकारी 37 देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन) पर भी भारत और चीन को लक्षित करने वाले शुल्कों का समर्थन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि पुतिन की युद्ध मशीन को रोकने के लिए एक एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है।

चीन ने रूस के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए टकराव से बचने की अपनी स्थिति को दोहराया है। विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत के दौरान भी यही रुख अपनाया था। स्लोवेनिया में उनकी टिप्पणियों ने वाशिंगटन की प्रतिबंध-आधारित नीति का सीधा विरोध किया।

ट्रंप ने इस युद्ध की जिम्मेदारी बाइडेन प्रशासन पर डाली है, यह कहते हुए कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू नहीं होता। उन्होंने यह भी दावा किया कि सामूहिक प्रतिबंध और रूसी तेल की खरीद बंद करने से युद्ध जल्दी खत्म होगा और हजारों जानें बचेंगी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि नाटो एकता के बिना, यह सब केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद, उन्होंने अभी तक मास्को पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिससे यूक्रेनी अधिकारी निराश हैं। इस बीच, रूस ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू होने के बाद से अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। ट्रंप के बयान से यह सवाल उठ रहा है कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं और अपने सहयोगियों से कितनी एकता हासिल कर सकते हैं।

यूएस में गवर्नर एबॉट का सख्त ऐलान

टेक्सास में शरिया कानून किया बैन सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ विवाद

टेक्सास **(एजेंसी)**। अमेरिका में टेक्सास राज्य के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने ऐलान किया है कि उनके प्रांत में शरिया कानून लागू करने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन 'शरिया अनुपालन' थोपने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस या टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी को सूचना दें।हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें ह्यूस्टन का एक मुस्लिम धर्मगुरु दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने की अपील करता दिख रहा है। गवर्नर एबॉट ने इस घटना को 'उत्पीड़न' बताया और कहा कि टेक्सास में सार्वजनिक जीवन में किसी भी धार्मिक कानून को थोपने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एबॉट ने 'एक्स' पर लिखा- ड'मैंने टेक्सास में शरिया कानून और शरिया कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति को ऐसे मूर्खों से डरना नहीं चाहिए।' उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई शरिया थोपने की कोशिश करता है, तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया जाए टेक्सास में पहले से कोई 'औपचारिक शरिया बैन' नहीं है। लेकिन 2017 में अमेरिकी कानून पारित किया गया था, जो अदालतों को किसी भी विदेशी या धार्मिक संहिता को लागू करने से रोकता है, अगर वह अमेरिकी कानून से टकराती है। इसी आधार पर शरिया कानून को भी लागू नहीं किया जा सकता।

मुस्लिम पैरोकार संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस ने एबॉट की टिप्पणियों को भ्रामक बताया।

नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति से चीन खुश, आधिकारिक तौर पर दी बधाई, कहा-और गहरी होगी पुरानी दोस्ती

बीजिंग **(एजेंसी)**। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चीन ने आधिकारिक तौर पर बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि नेपाल और चीन के बीच पुरानी और गहरी मित्रता है और बीजिंग हमेशा काठमांडू के फैसलों का सम्मान करता है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने बीते शुक्रवार को शपथ ली थी। इससे पहले नेपाल में एक हफ्ते तक हिंसक विरोध-प्रदर्शन चले थे, जिनके बाद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 'चीन, मैडम सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता है। चीन और नेपाल के बीच पुरानी मित्रता है और हम नेपाल के लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं।' प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि चीन नेपाल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों पर काम करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ाने तथा द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

यूक्रेन ने रूस की शीर्ष तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया

कीव **(एजेंसी)**। यूक्रेन ने बीती रात रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर भीषण ड्रोन हमला किया, जिससे आग लग गई। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। रूस के उत्तर-पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरिशी रिफ़ाइनरी पर बीती रात हुए हमले से हफ्तों पहले भी यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना को निशाना बनाया था। संबंधित प्रतिष्ठान हर वर्ष लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन या प्रतिदिन 3, 55, 000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार, घटनास्थल पर विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें रात के समय आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देता है। रूसी अधिकारियों ने हमले के परिणामों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना हुआ है,

लेकिन मांग में वृद्धि और यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण हाल के सप्ताहों में गैसोलीन की कमी हो गई है। देश के कुछ क्षेत्रों में ईंधन स्टेशनों पर ईंधन की कमी हो गई है और वाहन चालकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है।

इस कमी को कम करने के प्रयास में, रूस ने गैसोलीन के निर्यात पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने 30 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध और 31 अक्टूबर तक व्यापारियों तथा बिचौलियों को प्रभावित करने वाले आंशिक प्रतिबंध की बुधवार को घोषणा की।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)